खंड 2 – लोक नीति और विचारधारा

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 5 : लोक नीति पर राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव*

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 राजनीतिक विचारधारा का अर्थ और स्वरूप

5.3 लोक नीति पर राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव

5.4 प्रचलित राजनीतिक विचारधारा और लोक नीति

5.5 नीति पर विचारधारा के प्रभाव का मूल्यांकन

5.6 निष्कर्ष

5.7 शब्दावली

5.8 संदर्भ लेख

5.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातें समझ सकेंगें:

- राजनीतिक विचारधारा का अर्थ और स्वरूप;
- राजनीतिक विचारधारा और लोक नीति के मध्य संबंध; और
- नीति पर विचारधारा के प्रभाव के मूल्यांकन की चुनौतियाँ।

5.1 प्रस्तावना

आम तौर पर ऐसा महसूस किया जाता है कि लोक नीतियों के निर्धारण में राजनीतिक विचारधारा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न यह है कि क्या राजनीतिक विचारधारा भारत जैसे देश में लागू हुई लोक नीतियों पर प्रभाव डालती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं से युक्त एक बड़ी आबादी है? शासक दल की राजनीतिक विचारधारा निश्चित तौर पर नीति प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है। हालांकि, यहां पर हम राज्य के स्वरूप के विभिन्न सिद्धांतों अर्थात् उदारवादी, मार्क्सवादी, नव–उदारवादी, इत्यादि पर चर्चा नहीं करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में इस पाठ्यक्रम की इकाई 3 में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। भले ही शासक दल नव–उदारवादी (Neo-liberal) या अविनाशितावादी (Conservationalist) होने का दावा करता हो,परंतु जब नीति उन्मुखता (Policy Orientation) की बात आती है, वह फिर भी अपने दल की विचारधारा की वकालत नहीं कर सकता।

*योगदान : डा. आर. के. सप्रू, प्रोफेसर, लोक प्रशासन (सेवानिवृत), पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

जैसा कि हम इस पाठ्यक्रम की पिछली इकाइयों में देख चुके हैं कि कैसे बहु-हितधारक हमारे शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; सरकार केवल शासन के विभिन्न कर्ताओं में से एक है। भारत जैसे एक बहुदलीय लोकतंत्र में सरकार के पास अपनी विचारधारा लोगों पर थोपने का विकल्प नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सांसदों (विधायकों) को कई बाहरी दबावों और आंतरिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से समर्थन प्राप्त नीतियों का चयन करने की स्वतंत्रता को कम कर देता हैं। इस इकाई में, राजनीतिक विचारधारा पर व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। यहां पर यह तर्क दिया जाएगा कि विचारधारा, वास्तव में, विधायी कुलीनों की भूमिका के विश्लेषण के लिए एक मूल्यवान साधन हो सकती है। यहां पर राजनीतिक विचारधारा और लोक नीति पर उसके प्रभाव के मध्य संपर्कों का परीक्षण भी किया जाएगा। सबसे पहले, इस इकाई में 'राजनीतिक विचारधारा' और 'प्रभाव' शब्दों को समझने की कोशिश की जाएगी।

5.2 राजनीतिक विचारधारा का अर्थ और स्वरूप

राजनीतिक विचारधारा मान्यताओं या लक्ष्यों का सुसंगत और स्पष्ट संग्रह है, जिसका सरकार (राजनीतिक दल) को अनुसरण करना चाहिए। सामाजिक अध्ययन में राजनीतिक विचारधारा को सामाजिक आन्दोलन, संस्था, वर्ग या बड़े समूह के नैतिक आदर्शों, सिद्धांतों, मतों, मिथकों या प्रतीकों का एक निश्चित संग्रह माना जाता है, समाज को कैसे काम करना चाहिए यह उसकी व्याख्या करती है, और एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था के लिए राजनैतिक और सांस्कृतिक खाका प्रस्तुत करती है।

राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक संस्कृति से भिन्न है, जो मान्यताओं और आदर्शों का एक सुसंगत और स्पष्ट संग्रह है। परंतु, राजनीतिक संस्कृति का संबंध उन माध्यमों से होता है, जिनके द्वारा सरकार को अपने उद्देश्यों या लक्ष्यों का अनुसरण करने के लिए उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, सत्तावादी बनाम संवैधानिक सरकार। इस प्रकार, राजनीतिक विचारधारा राजनीति और सरकार की भूमिका पर विभिन्न विचारों का एक संग्रह है। मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर संगतता (Consistency) राजनीतिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

ऑक्सफोर्ड (Oxford) अंग्रेजी शब्दकोश में 'प्रभाव' को ''एक वस्तु का जबरदस्ती दूसरी वस्तु के संपर्क में आने की क्रिया'' के तौर पर परिभाषित किया गया है। इसका तात्पर्य एक चिह्नित परिणाम या प्रभुता है। रॉसी और फ्रीमैन (Rossi and Freeman, 1993) द्वारा परिभाषित किया गया है कि, ''प्रभाव आकलन यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि हस्तक्षेप द्वारा उनके इच्छित प्रभाव उत्पादित होते हैं या नहीं। ऐसे अनुमान निश्चितता के साथ नहीं लगाए जा सकते, लेकिन संभावितता की भिन्न सतह के साथ ही लगाए जा सकते हैं''। व्यापक संदर्भ में, थॉमस डाई (Thomas Dye, 2004) ने लिखा है कि नीति और प्रभाव हमें नीति के निम्नलिखित परिणाम जानने में सक्षम बनाते हैं:

- कुछ विशिष्ट लक्ष्य स्थिति या समूह;
- लक्ष्य के अतिरिक्त स्थिति या समूह पर 'प्लवन प्रभाव'(Spillover Effects);
- भविष्य के साथ-साथ तात्कालिक परिस्थितियाँ;
- प्रत्यक्ष लागत, कार्यक्रम के लिए समर्पित संसाधनों के संदर्भ में; और
- अप्रत्यक्ष लागत, जिसमें अन्य काम करने के अवसरों का नुकसान भी शामिल है।

प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य हस्तक्षेप द्वारा उत्पादित होने वाले निर्धारित प्रभाव का अनुमान लगाना है। क्योंकि, मूल्यांकन इसका परीक्षण करता है कि लोक नीति ने जैसा इरादा किया था वैसा कार्य किया है या नहीं। नीति प्रभाव यह मापता है कि लोक नीति ने संबोधित समस्याओं को वास्तव में कितना प्रभावित किया है।

5.3 लोक नीति पर राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव

राजनीतिक विचारधाराओं के दो आयाम होते हैं: i) लक्ष्य; और ii) विधि। समाज को कैसे संगठित होना चाहिए यह लक्ष्यों से संबंधित होता है। विधियाँ लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त तरीका होती हैं। कुछ राजनीतिक विचारधाराएं हैं: अराजकतावाद, समुदायवाद, साम्यवाद, रूढ़िवाद, लोकतंत्र, फ़ासीवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद, लोकवाद, समाजवाद, परा–मानवतावादी राजनीति (Transhumanist Politics) और धार्मिक-राजनीतिक विचारधाराएँ।

ऊपर उल्लेखित दो आयामों के अतिरिक्त, एक विचारधारा में चार बुनियादी विशेषताएं होती हैं। सरल वामपंथी-दक्षिणपंथी विश्लेषण से हटकर उनके अतिरिक्त, उदारवाद, रूढ़िवाद, स्वेच्छातंत्रवाद और लोकवाद संयुक्त राज्य अमेरिका में चार सबसे सामान्य विचारधाराएं हैं, इसके अतिरिक्त जो खुद को संयत (Moderate) के रूप में पहचानते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कई राष्ट्र ऐसी विशेष विचारधाराएं अपनाते हैं, जो काफी अस्पष्ट और असंदिग्ध होती हैं। परंतु यह विचारधाराएं दिल और दिमाग को आकर्षित करती हैं, और इस प्रकार, उन राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उनके इच्छित उद्देश्यों को सुरक्षित करने में मदद करती हैं। इन संदिग्ध विचारधाराओं को साम्राज्यवाद विरोधी विचारधाराओं के रूप में जाना जाता है, क्योंकि विश्व के अधिकांश राष्ट्र अपने विरोधी राष्ट्रों की कार्रवाहियों की साम्राज्यवादी कार्रवाहियों के रूप में निंदा करते हैं।

तीन अस्पष्ट और तथाकथित संदिग्ध (Ambiguous) विचारधाराएं हैं :

- राष्ट्रीय आत्मनिर्माण की विचारधारा;
- संयुक्त राष्ट्र की विचारधारा; और
- अमन और मानव अधिकार की विचारधारा।

पाकिस्तान की राजनीतिक विचारधारा का उदाहरण देते हुए ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान जम्मू व कश्मीर (वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश) के लोगों के खिलाफ काम कर रहे आतंकवादियों को दिए गए अपने समर्थन को सही ठहराने के लिए अपने राष्ट्रीय आत्मनिर्माण और आजादी के संघर्ष का तर्क प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि, वह अफगानिस्तान में अमरीकी कार्यवाही के समर्थन की अपनी नीति को सही ठहराने के लिए तालिबान विरोधी (Anti-Talibanism) तर्क का इस्तेमाल करता है, जिसमें अफगानिस्तान में अमरीकी कार्यवाही के लिए सैन्य समर्थन प्रदान करने का उसका निर्णय सम्मिलित है। अमेरिका ने इराक (Iraq) पर हमला करने और कब्जा करने के अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए परमाणु प्रसार निरोध (Non-Proliferation) के सिद्धांत का उपयोग किया है।

इस उदाहरण से, यह माना जा सकता है कि विरोधियों की नीतियों का आलोचन विश्व शांति के हितों को अनदेखी करने वाली नीतियों के रूप में किया जाता है। यहाँ तक कि जब कोई राष्ट्र किसी सैन्य कार्रवाई में संलग्न होता है, या किसी दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप

कर रहा हो, तब भी वह अपनी कार्यवाही को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्थाई अमन और स्थिरता के पक्ष को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक कार्यप्रणाली के रूप में समझाने और सही ठहराने का प्रयास करता है। ऐसा अमेरिका द्वारा 1991 में खाड़ी युद्ध (Gulf War) के दौरान किया गया था। आज भी 21वीं सदी में (इराक और अफगानिस्तान में युद्ध जारी है)। इसलिए, राष्ट्रों द्वारा विचारधारा का इस्तेमाल उनके द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों की वास्तविक स्वरूप को शांतिपूर्ण इरादों के मुखौटे के पीछे छुपाने और दुनिया के हर कोने से लोगों की सद्भावना और समर्थन को आकर्षित करने के लिए किया जाता है।

क्या राजनैतिक विचारधारा लोक नीतियों को प्रभावित करती है? क्या सरकार अपने मतदाताओं की मांगों का अनुसरण करती है, और अगर व्यक्तिगत स्तर पर वैचारिक विस्थापन हो तो क्या वह प्रतिक्रिया देती है? राजनीतिक विचारधारा विशिष्ट नीति निर्णय के मार्गदर्शन के लिए प्रासंगिक लगती है (हिनीच ऐंड मुंगेर–Hinich and Munger, 1994), विशेष रुप से राज्य-अर्थव्यवस्था संबंधों में और राज्य, व्यवसाय-संघ और व्यक्तियों के मध्य संबंधों के विनिमय में सरकार की भूमिका के लिए। उदाहरण के लिए, एक अधिक वामपंथी विचारधारा राज्य द्वारा हस्तक्षेप के पक्ष में और श्रमिकों की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उदाहरण स्वरूप, रोजगार संरक्षण के विषय में। दूसरी ओर, उदारवादी या दक्षिणपंथी (Right Wing) विचारधारा विपरीत वैचारिकी रखती है। भले ही दोनों को सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़े, विभिन्न विचारधाराओं से व्युत्पन्न नीति प्रक्रियाएं पृथक होती हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण 2008 का वित्तीय संकट है, जब विभिन्न वैचारिक प्रवृत्तियों ने संकट के प्रति विभिन्न समाधान पेश किए थे और कार्य प्रणाली में कुछ सरकारें प्रोत्साहन (Support) कार्यक्रमों में व्यस्त थीं, जबकि कुछ मितव्ययिता (Goodwill) में।

नागरिकों की विचारधारा और लोकनीति के मध्य अंतर्निहित निकटता यह है कि व्यक्तिगत विचारधारा राजनीतिक विचारधारा में एकत्र की जा सकती है। यह स्वयं को चुनाव में मतदान देकर व्यक्त करती है, जिसके द्वारा नागरिकों की विचारधारा औपचारिक रूप से सरकार की पक्षपातपूर्ण संरचना में स्थानांतरित होती हैं। एक निश्चित वैचारिक स्वरूप वाली सरकार निश्चित नीतियों को परिचित कराती है, उदाहरण के लिए, वामपंथी सरकारों के संदर्भ में व्यापार में अधिक सरकारी हस्तक्षेप (डाउन्स–Downs, 1957)। निवेश पक्ष पर विभिन्न विचारधाराएं पृथक नीति निवेश के रूप में स्थानांतरित होती हैं, यहां तक कि विभिन्न राजनैतिक परिणामों में भी। चुनी हुई सरकार द्वारा लोक नीति में परिवर्तन से पहले नागरिकों की विचारधारा में परिवर्तन होना चाहिए। विभिन्न वैचारिक प्रवृत्तियों वाली सरकारें क्या वास्तव में अपनी नीतियों में पृथक होती हैं? सवाल यह है कि, वास्तव में क्या राजनीतिक विचारधारा लोक नीतियों को प्रभावित करती हैं या नहीं?

व्यक्तिगत राजनीतिक विचारधारा भी चुनावी प्रणाली को नजरअंदाज करके भी, नीति को प्रभावित कर सकती है। एंथनी डाउन्स (Anthony Downs, 1957) द्वारा उल्लेखित औसत मतदाता सिद्धांत (Median Voter Theory) यह अनुमान लगाता है कि, वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों सरकारों द्वारा अनुसरण की गई नीतियां मध्य की ओर अभिसिंचित होती हैं। इसलिए, अंत में उनकी नीतियां उनके राजनीतिक वैचारिक वर्गीकरण के बावजूद अधिक पृथक नहीं होतीं। यदि मतदाता वामपंथ की ओर चला जाए, तो कौन सा शासक दल सरकार में है, इसकी परवाह किए बिना अधिक वामपंथी नीतियों का पालन करेगा। यह द्विदलीय प्रणाली (Two-Party Systems) के संदर्भ में सत्य है, परंतु उन प्रणालियों के लिए भी सत्य है, जिनमें शासन दलों का गठबंधन (Coalition of Parties)– वामपंथी खंड और दक्षिणपंथी खंड–आपस में प्रतिस्पर्धा का व्यवहार करता है और परिणामस्वरूप राजनैतिक कार्यालय ग्रहण (Occupy) करता है।

5.4 प्रचलित राजनीतिक विचारधारा और लोक नीति

जिस प्रश्न कि यहां पर जांच की जानी चाहिए, वह है कि क्या लोकप्रिय विचारधारा लोक नीतियों को प्रभावित करती है? दूसरे शब्दों में, क्या लोकप्रिय राजनीतिक विचारधारा, जो सरकार और उसकी नीतियों को मतदाताओं से गतिरोध पैदा करने वाले चुनावी संपर्क को संचालित करती है, उसका कोई प्रभाव है? तीन नीतियों पर लोकप्रिय और सरकारी विचारधारा के प्रभावों के लिए निम्नलिखित विश्लेषण परीक्षण हैः रोजगार सृजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक व्यय, और सरकार का आकार।

हालांकि, विश्लेषण के लिए चुनी गई यह तीन नीतियां इस विशेषता को साझा करती हैं कि एक वामपंथी झुकाव वाली जनसंख्या इनमें से प्रत्येक के लिए लोक कल्याण की मांग व्यक्त करती है। वह इस सवाल के बारे में पृथक विचार रखते हैं कि क्या सरकार की अभिरुचि विलियम निस्कानन (William Niskanen) के लोक नौकरशाही संबंधी तर्क पर आधारित है या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि निस्कानन ने 1968 में बजट-अधिकतम मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके मुताबिक उन्होंने सुझाव दिया कि तर्कसंगत नौकरशाह हमेशा और हर जगह अपने बजट को बढ़ाने के लिए स्वयं को सत्ता में लाना चाहते हैं। इससे राज्य की वृद्धि होगी, परंतु सामाजिक दक्षता कम होगी। रोजगार सृजन की नीतियां स्थापित करते समय राज्य ऐसे नियम स्थापित करता है, जिसमें दूसरे कर्ता, विशेष रूप से न्यायालय और जांच संस्थाएं, बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसलिए, ऐसा माना जाता है कि भले ही वामपंथी और दक्षिणपंथी सरकारों में मतभेद हो, फिर भी मुक्त राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, जो अपनी खुद की कार्यावली का अनुसरण करती है, बिना इन सरकारी मतभेदों के, खुद को वे दो अन्य नीतियों द्वारा व्यक्त कर सकेंगी।

परंतु, सरकार की राजनीतिक विचारधारा आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए प्रासंगिक मानी जाती है (हिब्स–Hibbs, 1977)। उसी प्रकार पूल व रोसेंथल (Pool and Rosenthal, 1997) का अध्ययन नीतियों पर विचारधारा का प्रभाव दर्शाता है। हालांकि, विचारधारा चुनाव आचरण में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पाया गया है, परंतु वह विभिन्न कारकों में से केवल एक है। कई बार परिस्थिति विपरीत तर्क के पक्ष में भी होती है यानी, शासक दल अपने राजनीतिक कार्यक्रमों और विचारधारा को अपेक्षाकृत अस्पष्ट और व्यापक तरीके से प्रतिपादित करते हैं, ताकि वह मतदाताओं को वैचारिक प्रवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला के मध्य आकर्षित कर सकें (मैलोनी और पिकरिंग–Maloney and Pickering, 2008)। ऐसा माना जाता है कि नागरिक किसी दल को देश की प्रमुख समस्याओं के मद्देनजर रखकर मतदान करते हैं (स्वैन्क–Swank, 1993)। मुद्दा यह है कि, लोकप्रिय विचारधारा और नीति के मध्य सरकारों के संबंधों की संरचना पर निर्भरता के कम साक्ष्य (Evidence) हैं।

इस विश्लेषण से ऐसी समीक्षा की गई है कि यह तीनों नीतियां अंतर–सहसंबंध हैं, परंतु विभिन्न कारकों के द्वारा इन्हें अलग-अलग प्रकार से समझाया गया है; यह सभी कारक राज्य और अर्थव्यवस्था के मध्य संबंध को प्रभावित करते हैं; और यह आर्थिक विकास, प्रसिद्ध विचारधारा और सरकारी संरचना जैसे कारकों से भी संबंधित हैं। प्रसिद्ध विचारधारा के विषय में निष्कर्ष बताते हैं कि वह रोजगार संरक्षण को प्रभावित करती है, परंतु न तो वह कल्याणकारी राज्य और न ही सरकार के आकार को प्रभावित करती हैं।

सरकारी संरचना (Composition) के प्रभाव के विषय में सरकार का वैचारिक अभिविन्यास इन तीनों विचाराधीन नीतियों में से किसी के भी संदर्भ में अधिक मायने नहीं रखता। सरकार

की विचारधारा राज्य-अर्थव्यवस्था संबंध में अधिक मायने नहीं रखती, और न ही कर्मचारियों और नियोक्ताओं के मध्य कानूनी संबंधों के विनियमन में। पिछले दशकों में इन नीतियों में से प्रत्येक में वास्तविक विकास हुआ है। रोजगार संरक्षण के विपरीत सामाजिक व्यय और सरकार का आकार दृढ़ता पूर्वक प्रचलन में हैं।, परंतु जनसंख्या में वामपंथी स्वरूप की ओर प्रत्यक्ष वैचारिक परिवर्तन नहीं होने के कारण दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है।

राजनीति, संघर्षों का प्रबंधन है। नीति निर्माता नीति विश्लेषण पर कम भरोसा करते हैं। उनके लिए एक राजनीतिक दृश्टिकोण तर्कसंगत दृष्टिकोण से बेहतर होता है। समझौता, सुलह, और मामूली अमिश्रित लाभ को स्वीकार करने की इच्छा संघर्ष समाधान का आधार निर्मित करते हैं। परस्पर लाभकारी परिणामों की खोज ('यदि आप मेरे प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, तो मैं आपके प्रस्ताव का समर्थन करूंगा) और विविध समूहों के मध्य मोल-भाव करना राजनीतिक दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य होता है।

राजनीतिक दृष्टिकोण में राजनीति, नीति विश्लेषण के लिए एक विकल्प बनाती है। अधिक से अधिक नीति विश्लेषण केवल एक माध्यमिक भूमिका निभाते हैं, परंतु यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संदर्भ में (लिंडब्लॉम और वुडहाउज–Lindblom and Woodhouse, 1993) कहते हैं कि, 'राजनीतिक प्रतिभागियों के बीच रणनीतिक विश्लेषण और आपसी समायोजन अंतर्निहित प्रक्रियाएं होती हैं, जिनके द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बुद्धिमत्तापूर्ण कार्रवाई (Intelligent Action) का स्तर हासिल करती हैं। क्योंकि समय, ऊर्जा और बौद्धिक क्षमता सीमित हैं, इसलिए रणनीति-संबंधी विश्लेषण को किसी समस्या के उन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, जिसे भाग लेने वाले विचारक एक दूसरे को मनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं।

राजनीति का नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, परंतु राजनीति किस हद तक नीति परिणामों को प्रभावित करती है? क्या यह वास्तव में समस्याओं को हल करने या उन्हें सुधारने के दृष्टिकोण से महत्व रखती है? भारत में नीति परिणाम पर किए गए हाल ही के शोध यह दर्शाते हैं कि आर्थिक और औद्योगिक परिणामों (सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जी. एन. पी. (GNP - Gross National Programme, रोजगार, मुद्रास्फीति (Employment, Inflation etc, इत्यादि) पर सरकार की नीतियों का प्रभाव व्यापक कारकों, जैसे अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव की तुलना में ज़्यादा सीमांत/हाशिए पर है। इसके अतिरिक्त,तथ्य यह है कि नीति निर्धारण और कार्यान्वयन पिछली नीतियों और पहले के फैसलों के संदर्भ में संगठित किए जाते हैं, जो गंभीर रूप से विकल्प और नवरचना को सीमित कर देते हैं।

हालांकि, उसी प्रकार सत्तारूढ़ दल का नीति पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, परंतु वह गंभीर रूकावटों जैसे कि लोकमत, नौकरशाही और राष्ट्रीय नीतियों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के कारण अधिक नीतिगत परिवर्तन नहीं ला सकता। संक्षेप में,''उदार लोकतांत्रिक सरकारें सीमांत पर काम करती हैं, उन घटना क्रमों, जिन्हें वह संचालित नहीं करती और जिसका वे पूर्वाभास नहीं कर सकती उन पर प्रतिक्रिया देने का प्रयास करती हैं''। डी बोनो (De Bono, 1991) ने यह भी तर्क प्रस्तावित किया है कि, नीति निर्धारण अक्सर जिसे वह अंतिम उद्देश्य ('Rear-end' Objectives) के रूप में परिभाषित करते हैं, उसके प्रति परस्पर प्रतिक्रियों की तुलना में उद्देश्यों की ओर बढ़ने के लक्ष्य से कम संचालित होता है। बेषक,चार्ल्स लिंडब्लॉम (Charles Lindblom) जिसे 'मडलिंग थ्रू' (Muddling Through) के रूप में परिभाषित करते हैं, नीति उसका ही परिणाम हो सकती है (नीति निर्माण में वृद्धिशीलता (Incrementalism) का सिद्धांत; जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए छोटे–छोटे कदमों

(Baby Steps) में विश्वास रखता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत नीतिगत बदलाव ज्यादातर परिस्थितियों में क्रांतिकारी के बजाय विकासवादी होते हैं। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि नीति निर्धारण का कोई मूल्य नहीं होता। लोक प्रबंधक एक संगठन के भीतर कमजोर क्षेत्रों की पहचान और उनमें सुधारात्मक परिवर्तन करते हैं।

बोध प्रश्न 1

नोट : i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. 'राजनीतिक विचारधारा' शब्द को परिभाषित कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. लोक नीति पर राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5.5 नीति पर विचारधारा के प्रभाव का मूल्यांकन

सरकार पर नीति कार्यक्रम के प्रभाव के मूल्यांकन में आने वाली समस्याएं प्रत्येक देश में विविध और हर देश में अलग–अलग होती हैं। कुछ उल्लेखनीय समस्याओं पर यहां संक्षिप्त में चर्चा की गई है:

नीति प्रभाव के विश्लेषण में विविधताएं (Variations in Analysis of Policy Impact)

उत्पाद और परिणाम दोनों मापन महत्वपूर्ण हैं, परंतु भिन्न कारणों के लिए। यह जवाब देना की नीति का क्या प्रभाव पड़ा है, कठिन है। उदाहरण के लिए, 'जीवन की गुणवत्ता' पर नीति कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन इस अवधारणा को बताता है कि 'जीवन की गुणवत्ता' का असल मतलब क्या है। जेम्स विल्सन (James Wilson, 1973) ने यह तर्क दिया है कि, लोक नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण इस पर आकस्मिक है कि 'आप किस परिस्थिति में हैं' ('Where you Sit')। उनके अनुसार यदि शोध, नीति को लागू करने वालों द्वारा किया जाए, तो वह दर्शाएगा कि उसने सही परिणाम दिए हैं।

दूसरी ओर, यदि अनुसंधान या शोध स्वतंत्र विश्लेषकों द्वारा किया जाए, तो वह नकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। दूसरे शब्दों में, नीति की समस्याओं पर वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन तथ्यों की बजाए, ज्ञान और मूल्य की विषयवस्तु है। सरकार में प्रभावी मूल्यांकनकर्ताओं में

सामान्यतः अनुसंधान क्षमताओं की कमी होती है। अस्पष्टता, तुलना के लिए उपयुक्त आधार की कमी और ठोस साक्ष्यों की कमी मूल्यांकन के समय प्रशासक के नियंत्रण को बढ़ाती है, या कम से कम विफलता की स्थिति में आलोचना को कम करती है।

नीति प्रभाव में राजनीतिक प्रभुता (Political Influence on Policy Impact)

अक्सर, यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि, नीति के परिणाम राजनीतिक प्रभुता के प्रतिफल हैं। जब नीति-निर्माता नीतियों का स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इत्यादि के क्षेत्रों में प्रभाव की पूछताछ या शोध करते हैं, तो वह उसके संदर्भ और कार्यसूची, जिसमें समस्याओं की परिभाषा और उनका निर्माण किया जाता है, को आकार देते हैं। इसलिए इस तात्पर्य में, प्रभाव मूल्यांकन हमें नीति प्रक्रिया की शुरुआत में ले जाते हैं। इसका अर्थ है कि प्रभाव के दावों और निर्माणों को आकलन का सामना करना पड़ता है, जिसे अन्य राजनैतिक दलों, प्रभावक समूहों, प्रबुद्ध मंडलों, शोधकर्ताओं, इत्यादि द्वारा परिनियोजित किया जाता है, जो यह देखना चाहते हैं कि कोई नीति कैसे काम नहीं कर रही, ताकि वह अपने दावों को सही साबित कर सकें। लिंकन और गुबा (Lincoln and Guba, 1985) के अनुसार, जो प्रभाव आकलन में मात्रात्मक दृष्टिकोण के आलोचक हैं, 'किसी नीति/कार्यक्रम के प्रभाव मूल्यांकन के राजनीतिक स्वरूप का अर्थ है कि स्पष्ट रूप से लक्ष्यनिश्ठ तथ्यों के विकृत प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए मूल्यांकन के अधिक गुणात्मक रूप की आवश्यकता है'।

नीति परिणामों की तुलना में जटिलता (Complexity in Comparison of Policy Outcomes)

विभिन्न राष्ट्र भिन्न आंकड़ों का उत्पादन और उपयोग करते हैं, और इन आंकड़ों का विशिष्ट संदर्भ होता है। परंतु आंकड़ों की श्रेणियों की तुलना एक बहुत ही कठिन कार्य है। हालांकि, नीति परिणामों की तुलना की अवधारणा में ऐसी स्पष्ट पद्धति संबंधी समस्याएं होती हैं। आधुनिक विश्व के संदर्भ में, परिणामों की तुलना अंतरराष्ट्रीय संस्थानों –जैसे विश्व बैंक (World Bank,) और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)–द्वारा उत्पादित आंकड़ों के प्रयोग से की जाती है। नीति विश्लेषक और राजनेता जानना चाहते हैं कि क्यों विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं वास्तविक परिणामों के संदर्भ में भिन्न होती हैं? क्यों देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का निश्चित अनुपात स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा, इत्यादि क्षेत्रों पर खर्च करते हैं? क्यों नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन और प्रदर्शन राष्ट्र-दर-राष्ट्र भिन्न होता है? हालांकि, ऐसे सवालों का स्पष्टीकरण भिन्न और जटिल होता है।

इसके अतिरिक्त, लोक प्रशासन में प्रभाव और मूल्यांकन का अध्ययन गंभीर रूप से उपेक्षित रहा है। यह न केवल रूचि और नवाचार की कमी से ग्रस्त है, परंतु, कार्यप्रणाली के मोर्चे पर कमियों से भी ग्रस्त है। प्रभाव का विश्लेषण और मानकों का निर्धारण करते समय नीति निर्माता अतीत के अनुभवों से तुलना पर भरोसा करते हैं। ड्रॉर (Dror, 1989) का कहना है कि, कई मामलों में, अतीत से तुलना भ्रामक होती है, क्योंकि यह विश्वसनीय निष्कर्ष के लिए एक 'शून्य बिंदु'(Zero Point) प्रदान नहीं करती। विशेष रूप से भारत के अनुभव ने, इस बात को दर्शाया है कि भारत से भिन्न देशों से लिए गए सफल आदर्श मॉडलों ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि विविध आर्थिक नीतियां सामाजिक सुधार पर अपना प्रभाव बनाने में असफल रही हैं।

बोध प्रश्न 2

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपना उत्तर मिलाइए।

1. नीति पर विचारधारा के प्रभाव के मूल्यांकन में आने वाली समस्याओं की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5.6 निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि, राजनीतिक विचारधारा, लोक नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन में एक अहम भूमिका निभाती है। इसका इस्तेमाल किसी राष्ट्र द्वारा अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए या फिर अन्य राष्ट्रों, विशेष रूप से, विरोधियों की नीतियों की आलोचना और उन्हें अस्वीकार करने के लिए किया जाता है। विचारधाराओं को सरकारों द्वारा अपने असली इरादों को छुपाने के लिए एक आवरण के रूप में देखा जाता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपनी शक्ति की वृद्धि और उसको बनाए रखना सम्मिलित है। प्रत्येक विदेश नीति, विशेष विचारधाराओं की एक श्रंखला को रक्षा और आक्रमण के वैचारिक हथियारों के रूप में इस्तेमाल करती है।

जैसा कि विवेचन किया गया है कि विचारधारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और संघर्ष दोनों का स्रोत होती है। वह राष्ट्र जिनके सामान्य वैचारिक झुकाव होते हैं, वह अक्सर एक-दूसरे के साथ सहयोग की स्थिति में होते हैं। दूसरी तरफ वैचारिक मतभेद, विशेष रुप से भिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंधों में अक्सर तनाव के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।

इसका यह अर्थ नहीं है कि विचारधारा अंतरराष्ट्रीय मामलों में कोई भूमिका नहीं निभाती। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों की कार्यप्रणाली और अंतर्वस्तु को प्रभावित करने वाले कारकों में से केवल एक है। समकालीन समय में, विचारधारा राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपनी अवधारणाओं का संचार करने और कार्रवाई करने के लिए कुछ साधन, अवधारणाएं और परिभाषाएं प्रदान करती हैं। विचारधाराएं राष्ट्रों द्वारा अपनी नीतियों और कार्यवाई को समझाने और सही ठहराने के लिए उपयोग की जाती हैं। यह विश्व के हर राष्ट्र के नीति निर्माताओं को उनके राष्ट्र हित के लक्ष्यों के निर्माण, औचित्य और सुरक्षा के लिए एक आधार प्रदान करती है। कुछ लोगो का मानना है कि वैष्वीकरण के चलते, विचारधारा की भूमिका अधिक से अधिक प्रभावहीन हो रही है।

5.7 शब्दावली

अराजकतावाद (Anarchy) : यह मान्यता सभी प्रकार की सरकारों के उन्मूलन में विश्वास रखती है। यह बिना किसी बल या मजबूरी के और सहकारी तरीके से अन्य प्रकार के शासन तंत्र के उन्मूलन में भी विश्वास रखती है।

समुदायवाद (Communitarianism) : वह जो व्यक्ति और समुदाय के मध्य संबंध को महत्व देता है। इसके अनुसार, समाज में सामुदायिक संबंध किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार प्रदान करते हैं।

साम्यवाद (Communism) : वह सिद्धांत या सामाजिक संगठन की प्रणाली, जिसमें समुदाय को सारी संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त होता है। इस प्रकार के समाज में लोग अपनी क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार योगदान देते व लेते हैं।

रूढ़िवाद (Authoritaranism) : एक धारणा, जो पारंपरिक मूल्यों और अवधारणाओं पर आधारित है।यह सभी प्रकार के परिवर्तनों और नवाचार का विरोध करती है।

फासीवाद (Fascism) : यह एक अत्यधिक दक्षिणपंथी तानाशाही और सत्तावादी व्यवस्था होती है। यह अति-राष्ट्रवाद **(Ultra Nationalism)** और सख्त अनुशासन तथा विपक्ष के उत्पीड़न पर आधारित है।

स्वेच्छातंत्रवाद (Libertarianism) : इसके अनुसार, राज्य द्वारा समाज में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह अहस्तक्षेप (Laissez-Faire) के संदर्भ में लोगों के जीवन में निम्न हस्तक्षेप में विश्वास करता है।

उदारवाद (Liberalism) : यह एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है, जो स्वतंत्रता, सहमति और समानता पर आधारित है।

लोकवाद (Populism) : एक दृष्टिकोण जो आम लोगो को आकर्षित करता है, जिन्हें यह महसूस होता है कि कुलीन समूहों और हितों द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है।

समाजवाद (Socialism) : यह एक आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था है। इसके अनुसार, उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता का स्वामित्व और संचालन श्रमिकों द्वारा होना चाहिए न कि निजी समूहों द्वारा।

परा–मानवतावादी राजनीति (Trans-humanist Politics) : यह राजनीतिक विचारधाराओं के एक समूह का गठन है, जो आम–तौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव में सुधार पर विश्वास व्यक्त करता है।

5.8 संदर्भ लेख

De Bono, E. (1981). *Atlas of Management Thinking*.London: Temple Smith.

Downs. A. (1957). *An Economic Theory of Democracy.* New York: Harper.

Dror, Y. (1989). *Public Policymaking Re-examined.* New Jersey: Transaction Publishers.

Dye, T.R. (2004). *Understanding Public Policy.*New Jersey: Prentice Hall.

Entman, R. (1983). Impact of Ideology on Legislative Behaviour and Public Policy. *Journal of Politics*.45, 163-182.

Hibbs, Jr. D.A. (1977). Political Parties and Macroeconomic Policy.*American Political Science Review.*71, 1467-1487.

Hinich. M.J. & Munger, M.C. (1994). *Ideology and the Theory of Political Choice.* Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Lincoln, Y.S. &Guba, E.G. (1985). *Naturalistic Inquiry.* California: Sage.

Lindblom, C. & Woodhouse, E.J. (1993). *The Policy-making Process.* New Jersey: Englewood Cliffs.

Maloney, J.& Pickering, A. (2008). *Ideology Competence Luck: What Determines General Election Results?* Discussion Paper No. 08è607. Bristol: University of Bristol.

Poole, K & Rosenthal H. (1997). *Congress: A Political Economic History of Roll Call Voting.* New York: Oxport University Press.

Rossi, P.H. & Freeman, H. (1993). *Evaluation: A Systematic Approach.* California: Sage.

Swank, O. (1993). Popularity Functions Based on the Partisan Theory. *Public Choice.* 75, 339-356.

Wilson, J. (1973).*Organizations.*California: Sage.

5.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न-1

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:**

   - राजनीतिक विचारधारा मान्यताओं या लक्ष्यों का सुसंगत और स्पष्ट संग्रह है, जिसका सरकार (राजनीतिक दल) को अनुसरण करना चाहिए।
   - राजनीतिक विचारधारा सामाजिक आन्दोलन, संस्था, वर्ग या बड़े समूह के नैतिक आदर्शों, सिद्धांतों, मतों, मिथकों या प्रतीकों का एक निश्चित संग्रह होता है।
   - राजनीतिक विचारधारा समाज को कैसे काम करना चाहिए, उसकी व्याख्या करती है और एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था के लिए राजनैतिक और सांस्कृतिक खाका प्रस्तुत करती है।
   - राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक संस्कृति से विभिन्न है, जो मान्यताओं और आदर्शों का एक सुसंगत संग्रह है।
   - राजनीतिक संस्कृति का संबंध उन माध्यमों से होता है, जिनके द्वारा सरकार को अपने उद्देश्यों या लक्ष्यों का अनुसरण करने के लिए उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, सत्तावादी बनाम संवैधानिक सरकार।
   - राजनीतिक विचारधारा राजनीति और सरकार की भूमिका पर विभिन्न विचारों का एक संग्रह है। मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर संगति राजनीतिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

2. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिएः**

- तीन प्रकार की विचारधाराएं हैंः राष्ट्रीय आत्मनिर्माण की विचारधारा; संयुक्त राष्ट्रीय की विचारधारा; और अमन और मानव अधिकार की विचारधारा।
- यह तीनों विचारधाराएं परस्पर संबंधित हैं।
- यह तीन नीतियां इस विशेषता को साझा करती हैं कि एक वामपंथी प्रवृत्ति वाली जनसंख्या प्रत्येक से लोक कल्याण की मांग करती हैं।
- वह इस सवाल के बारे में पृथक विचार रखते हैं कि, 'सरकार की लोक नौकरशाही के आकार में अभिरूचि है या नहीं।
- नागरिकों की विचारधारा और लोक नीति के मध्य अंतर्निहित निकटता यह है कि व्यक्तिगत विचारधारा राजनीतिक विचारधारा में एकत्र की जा सकती है।
- यह स्वयं को चुनाव में मतदान देकर व्यक्त करती है, जिसके द्वारा नागरिकों की विचारधारा औपचारिक रूप से सरकार की पक्षपातपूर्ण संरचना में स्थानांतरित होती है।
- एक निश्चित वैचारिक प्रवृत्ति वाली सरकार निश्चित नीतियों को परिचित कराती है। उदाहरण के लिए, व्यापार में वामपंथी सरकारों के संदर्भ में अधिक सरकारी हस्तक्षेप और दक्षिणपंथी सरकारों के संदर्भ में कम।
- नीति निर्धारण और कार्यान्वयन पिछली नीतियों और पहले के फैसलों के संदर्भ में संगठित किए जाते हैं, जो गंभीर रूप से विकल्प और नवरचना को सीमित कर देते हैं।
- लोक प्रबंधक एक संगठन के भीतर कमजोर क्षेत्रों की पहचान करते हैं और उनमें सुधारात्मक परिवर्तन करते हैं।

बोध प्रश्न-2

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए :**

- नीति प्रभाव के विश्लेषण में भिन्नता
- राजनैतिक प्रभुता में नीति प्रभाव
- नीति परिणामों की तुलना में जटिलता

इकाई 6 : नेहरूवादी दृष्टिकोण की विचारधारा और नीति*

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 नेहरूवादी दृष्टिकोण की विचारधारा और नीति का स्वरूप

6.3 नेहरूवादी दृष्टिकोण और शासी नीतियाँ

6.3.1 आर्थिक नीतियों पर नेहरूवादी दृष्टिकोण

6.3.2 कृषि नीतियों पर नेहरूवादी दृष्टिकोण

6.3.3 सामाजिक नीतियों पर नेहरूवादी दृष्टिकोण

6.3.4 लोक प्रशासन पर नेहरू के विचार

6.3.5 रक्षा और विदेश नीतियों पर नेहरूवादी दृष्टिकोण

6.4 निष्कर्ष

6.5 शब्दावली

6.6 संदर्भ लेख

6.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बाते समझ सकेंगेः

- नेहरूवादी दृष्टिकोण की विचारधारा और नीति के स्वरूप;
- लोक नीति के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण; और
- कृषि, परमाणु – प्रौद्योगिकी और सामुदायिक विकास से संबंधित विशिष्ट नीतियों से जुड़े नेहरूवादी पक्ष।

6.1 प्रस्तावना

जवाहरलाल नेहरू (1889-1964) जिनके साथ 'नेहरूवाद' शब्द सहयुक्त है, उन्होंने कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्शों को प्रमाणित किया। इन आदर्शों को उनकी स्वतंत्र भारत की दूरदर्शिता में स्थान प्राप्त हुआ। नेहरू किशोरावस्था से ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे और वे 1910 के उथल–पुथल भरे दशक में भारत की राजनीति में एक उभरती हस्ती बन गए। 1929 में अपने गुरु, महात्मा गांधी, की अनकही पर निश्चित मंजूरी के साथ नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस दल के अध्यक्ष के तौर पर नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय

*योगदान : डा. आर. के. सप्रू, प्रोफेसर, लोक प्रशासन (सेवानिवृत), पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता या ब्रिटिश राज से 'पूर्ण स्वराज' की मांग का आहवान किया और कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा को निर्णायक मोड़ प्रदान किया।

1930 के दशक के दौरान जैसे-जैसे देश आजादी की ओर अग्रसर हो रहा था, एक प्रतिबद्ध राष्ट्रवादी के रूप भारत की राजनीति में नेहरू और कांग्रेस दोनों का प्रभुत्व था। नेहरू भारत को पश्चिमी देशों की तरह औद्योगिक रूप से प्रगति करते देखना चाहते थे, लेकिन समानता, निश्पक्षता, सामाजिक न्याय और आजादी के विचारों पर समझौता किए बिना। यह इकाई नेहरूवादी दृश्टिकोण की विचारधारा और नीति के स्वरूप को समझाने का प्रयास करेगी। यह भारत की सामाजिक, कृषि, विदेशी और आर्थिक नीतियों पर नेहरू के दृष्टिकोण की भी चर्चा करेगी। हम इस पाठ्यक्रम में नेहरू की नीतियों की दृश्टि के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारत में नीति की नींव रखी थी। नेहरू के दृष्टिकोण और नीति की दृष्टि की समझ के बिना, आज देश में लोक नीति के स्वरूप और सार को समझना संभव नहीं है।

6.2 नेहरूवादी दृष्टिकोण की विचारधारा और नीति का स्वरूप

'नेहरूवाद' शब्द का सरल अर्थ स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थित एक दर्शन या विचारधारा है। राजनीतिक रूप से 'नेहरूवाद' का अर्थ 'धर्मनिरपेक्षता' 'वैज्ञानिक स्वभाव' और 'समावेशी उदारवाद' के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता है। आर्थिक दृश्टि से, 'नेहरूवाद' का अर्थ 'देश की अर्थव्यवस्था' की दिशा निर्धारण और 'नियोजित विकास' में सक्रिय 'राज्य हस्तक्षेप' का प्रतीक है। इसका अर्थ नीतियों का क्रियान्वयन है, जो 'फैबियन समाजवादी' (Fabian Socialist) के आदर्श और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के 'सोवियत मॉडल' का मिश्रण प्रदर्शित करता है। सामाजिक रूप से, 'नेहरूवाद' का अर्थ शोषित समुदायों की सामाजिक भलाई के लिए प्रतिबद्धता है।

आम वार्तालाप में, विचारधारा की बात करें, तो सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि ''आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मूल्यों और लक्ष्यों से संबंधित विचारों का एक निकाय, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियात्मक कार्यक्रम को सकारात्मक करता है''। सरल शब्दों में 'विचारधारा' राय और विश्वास की एक श्रेणी है, जो एक विशेष संस्कृति का चित्रण करती है। 'विचारधारा'विचारों का एक समूह है, जो अतीत को अर्थपूर्ण करने, वर्तमान को समझाने और भविष्य को बढ़ावा देने के लिए प्रयोजन करती है। दूसरे शब्दों में,'विचारधारा'विचारों या सिद्धांतों की वह श्रेणी है, जो विशेष रूप से एक घटना की व्याख्या करती है, किसी विशेष सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक क्रम का समर्थन या उन्हें अस्वीकृत करने के लिए (सप्रू–Sapru, 2015)।

ऑक्सफोर्ड शब्दकोष 'दृष्टिकोण' को 'कल्पना या ज्ञान से भविष्य की योजना या उसे सोचने की क्षमता' के रूप में परिभाषित करता है। सामान्य शब्दों में इसका अर्थ होता है, भविष्य क्या होगा और कैसा हो सकता है; उसकी एक मानसिक छवि। जवाहरलाल नेहरू को 'दूरदर्शी' नेता माना जाता है, जिन्होंने कल्पना और ज्ञान के साथ भारत के भविष्य के बारे में सोचा या उसकी योजना बनाई। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी माना जाता है।'नेहरूवाद', 'दृश्टिकोण' और 'विचारधारा'का अर्थ स्पष्ट करने के पश्चात् हम नेहरू के विचारों और धारणाओं को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।

हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन, जो अगस्त 1947 के बाद समाप्त हुआ, नेहरू को कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री के रूप में पद संभालने के लिए चुना गया था। उनके नेतृत्व का सवाल 1941 में पहले से ही सुलझ चुका था, जब गांधी ने नेहरू को

उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अभिस्वीकृति दे दी थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू, भारत के बारे में अपने दृष्टिकोण को साकार करने की यात्रा प्रारम्भ कर चुके थे। 26 जनवरी 1950 में संविधान को अपनाने के साथ, नेहरू ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। मुख्यरूप से उन्होंने अनेक या बहुदलीय प्रणाली की देखभाल करते हुए; एक उपनिवेश से एक गणतंत्र तक भारत का निरीक्षण किया।

नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में श्रेष्ठ, समावेशी पार्टी के रूप में उभरी, और 1951, 1957 और 1962 में लगातार चुनाव जीतती रही। नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल के अंतिम वर्षों में, राजनीतिक परेशानियों और 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान तथाकथित नेतृत्व की विफलता के बावजूद, वह भारत के लोगों में लोकप्रिय रहे। 27 मई 1964 को नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अपने जीवनकाल में कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ अपनी जड़ों के कारण उन्हें पंडित नेहरू के नाम से जाना जाता था, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते थे। आइए अब हम नेहरू की नीति और शासन के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

6.3 नेहरूवादी दृष्टिकोण और शासी नीतियाँ

जैसा कि हम सब जानते हैं, नेहरु ने 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल ग्रहण किया और अपना प्रसिद्ध ''नियति से वादा'' (Tryst with Destiny) शीर्षक से जाना जाने वाला उद्घाटन भाषण दिया था। यह भाषण इस प्रकार हैः ''कई सालों पहले, हमने नियति के साथ एक वादा किया था, और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभायें, पूरी तरह न सही पर बहुत हद तक तो निभायें। आधी रात के समय, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जागेगा। ऐसा क्षण आता है, मगर इतिहास में विरले ही आता है, जब हम पुराने युग से बाहर निकल नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है, तब एक देश की लम्बे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। यह संयोग ही है कि इस सत्यनिष्ठ अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं'' (नेहरू–Nehru, 1946)।

पारेख (Parekh, 1991) ने भारत के राष्ट्रीय दर्शन, के लिए इस उद्घाटन संबोधन को जिम्मेदार ठहराया है। जिसे नेहरू ने जिसे प्रतिपादित किया था। जैसा देखा गया है, नेहरू के लिए आधुनिकीकरण राष्ट्रीय दर्शन था, जो सात लक्ष्यों के साथ था। राष्ट्रीय एकता, संसदीय लोकतंत्र, औद्योगीकरण, समाजवाद, धार्मिक सद्भाव, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, और गुटनिरपेक्षता। नेहरू ने ''राज्य द्वारा प्रायोजित औद्योगीकरण, धन-उत्पादक क्षमता को बढ़ाने, और नागरिक उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने'' की वकालत की (दास–Das, 2011)। आइए अब हम विशिष्ट नीतियों पर उनके विचारों की चर्चा करते हैः

6.3.1 आर्थिक नीतियों पर नेहरूवादी दृष्टिकोण

नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) की वकालत की, जहां सरकार द्वारा नियंत्रित लोक क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ सह-अस्तित्व (Coexistence) में हो। उनका मानना था कि, बुनियादी और भारी उद्योग की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण और विकास के लिए मौलिक थी। इसलिए, सरकार ने मुख्य रूप से प्रमुख लोक क्षेत्र के उद्योगों

में निवेश का निर्देश दिया जैसे कि स्टील, लोहा, कोयला, और ऊर्जा; जिससे सब्सिडी और संरक्षणवादी (Subsidies and Protectionst) नीतियों के साथ विकास को बढ़ावा मिला। नीतियों को परिभाषित करने के क्षेत्र में नेहरू की दृष्टि अत्यधिक तीव्र रही। वे 1948 और 1956 के भारतीय औद्योगिक नीति प्रस्तावों के प्रमुख मस्तिष्क और लोक क्षेत्र की अवधारणा के प्रवर्तक थे। वह चाहते थे कि नीति विज्ञान की ओर उन्मुख हो, विशेष रूप से, परमाणु ऊर्जा की ओर। नेहरू ने देश में त्वरित से औद्योगिकीकरण की नींव रखी। उनकी दृष्टि और प्रयासों के कारण ही आज भारत को विश्व के प्रमुख तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्रों में से एक माना जाता है।

नेहरू के प्रबंधन के अन्तर्गत लोक क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी उन्नति हासिल की। संसद में, मई 1956 में उन्होंने कहा कि, ''वह चाहते थे कि संसद को यह पता चले कि लोक क्षेत्र कार्य करने के लिए कितना विशाल और अप्रयुक्त है, यदि निजी क्षेत्र के लोग भी आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि लोक क्षेत्र बुनियादी और रणनीतिक चीजों के संबंध में कायम रहे'' (सप्रू, *op.cit.*)।

इस प्रकार, यह नेहरू का दृढ़ विश्वास था कि गरीबी और देश से आर्थिक पिछड़ापन मिटाने में, एक महत्वपूर्ण सीमा तक, लोक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने निजी क्षेत्र की भूमिका को भी महत्व दिया। उन्होंने इसे भारत के आधुनिक औद्योगिक मंदिर (Modern Industrial Temples of India) कहा। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि, ''लोक और निजी क्षेत्र के मध्य विशेषता आपेक्षिक प्रमुखता की है... लोक और निजी क्षेत्र दो अलग-अलग संस्थाओं की तरह नहीं देखे जा सकतेः वे एक ही जीव के अंगों के रूप में हैं, और उन्हें ऐसे ही कार्य करना चाहिए''(खोसला–Khosla, 2015)।

नेहरू ने लोक उद्यमों के लिए पर्याप्त स्वायत्तता दी जानी की वकालत की। वह इन उद्यमों के लिए नौकरशाही प्रबंधन शैली के प्रयोग के खिलाफ थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि,''मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर लोक उद्यम पर इस तरह के सामान्य सरकारी प्रक्रिया लागू होती है, तो वह उस लोक उद्यम की विफलता को जन्म देगी। इसलिए, हमें लोक उद्यमों की कार्यप्रणाली के लिए एक व्यवस्था विकसित करनी होगी, जहां एक ओर, पर्याप्त जांच और संरक्षण हो, और दूसरी ओर, उस उद्यम को जल्दी और बिना देरी के काम करने की पर्याप्त स्वतंत्रता'' (*Ibid.*)।

वह कठोर संसदीय नियंत्रण के विरुद्ध थे।''हम हर दिन इस कक्ष (House) में नहीं बैठ सकते और यहां से लोक उद्यमों को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह अभी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम बहुत आग्रह–पूर्ण रहे तो हम पैसे का एक बड़ा सौदा खो देंगे और यह एक प्रकार का स्थैतिक वातावरण विकसित करेगा, जो बढ़ते उद्योग के लिए बहुत बुरा होगा'' (*Ibid.*)। इस प्रकार, नेहरू संसदीय नियंत्रण और लोक उद्यमों की स्वायत्तता के बीच उचित संतुलन हासिल करने के लिए इच्छुक थे।

हालांकि, उनके आलोचकों के अनुसार,बड़े राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों के लिए नेहरू की प्राथमिकता ने (मात्रात्मक नियमों), कोटा और सीमा-शुल्क, औद्योगिक लाइसेंस, और अन्य नियंत्रणों की एक जटिल प्रणाली बनाई। यह व्यवस्था भारत में परमिट या लाइसेंस राज (License Raj) के रूप में जानी जाती है, जो आर्थिक अक्षमताओं के लिए जिम्मेदार थी, इसने उद्यमशीलता को गति प्रदान की और दशकों तक आर्थिक विकास की जांच की, यह तब तक जारी रहा जब तक 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतष्त्व वाली कांग्रेस सरकार ने उदारीकरण की नीतियां लागू नहीं कर दीं। (यर्जिन और

स्टैनिस्लॉ–Yergin and Stanislaw, 2002)। फिर भी, मूल और बुनियादी क्षेत्रफलों में राज्य क्षेत्र के बारे में उनका दृश्टिकोण अपने समय से आगे का था और आज भी महत्व रखता है।

6.3.2 कृषि नीतियों पर नेहरूवादी दृष्टिकोण

नेहरू के नेतृत्व में सरकार ने तेजी से उद्योगीकरण के साथ कृषि सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने महसूस किया, जैसा कि देखा गया है, कि औद्योगीकरण की सत्तता के लिए एक सहायक कृषि अर्थव्यवस्था और एक छोटे पैमाने पर औद्योगिक आधार की जरूरत थी। नगर नियोजन (Town Planning) पर उनके विचार उल्लेखनीय रूप से आधुनिक थे। सड़कों और पार्कों से परे–शिक्षा, मनोरंजन, रोजगार और व्यवसाय मलिन बस्तियों ने उन्हे परेशान किया; उन्होंने शहर और गांव के बीच एक सहजीवी संबंध की कल्पना की (दास–Das, *op.cit.*)।

एक सफल भूमि सुधार नीति जिसने बड़ी–बड़ी जोतनीय कृषि भूमियों (Landholding) या भूमिस्वामित्व को समाप्त किया, लेकिन भूमि के स्वामित्व पर सीमाएं लगाकर भी भूमि के पुनर्वितरण के प्रयास बहुत हद तक सफल नहीं हुए। उनके नेतृत्व में, सरकार ने फिर से, बड़े पैमाने पर सहकारी कृषि शुरू करने का प्रयास किया। लेकिन इसके प्रयास ग्रामीण कुलीन वर्ग या जन–साधारण को पसंद नहीं आएं, उनके प्रयासों के विरोध में राजनीतिक समर्थन प्राप्त था। 1960 के दशक की शुरुआत तक कृषि उत्पादन का विस्तार हुआ, क्योंकि अतिरिक्त भूमि को खेती के तहत लाया गया था और कुछ सिंचाई परियोजना का असर होने लगा था। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना ने कृषि विकास में भी योगदान दिया। नेहरू के नेतृत्व के दौरान हरित क्रांति एक विशाल सफलता का प्रतीक था। इस क्रांति को विविधता लाने के प्रयास और फसल उत्पादन में वृद्धि के रूप में देखा गया। इसने उत्तरी भारत को गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म के एक बड़े निर्माता के रूप में बदल दिया। हालांकि, हरित क्रांति में, आलोचकों की अपनी राय रही है। अत्यधिक उर्वरक (Fertilizers) के प्रयोग के कारण कई पर्यावरणवादियों ने इसकी आलोचना की है। आर्थिक और क्षेत्रीय असमानताएँ पैदा करने के लिए भी हरित क्रांति की आलोचना की गई है। हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता इस क्रांति की प्रतीक थी। यह उत्पादन के नए उपकरणों और तकनीकों को सामने लाई और भारत को कृषि के उन्नत देशों के नक्शे पर रखा।

6.3.3 सामाजिक नीतियों पर नेहरूवादी दृष्टिकोण

जब हम सामाजिक नीतियों के बारे में बात करते हैं, तो हमारा तात्पर्य उन नीतियों से होता है, जो लक्षित जनसंख्या की सामाजिक स्थिति को बेहतर करने का उद्देश्य रखती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी लाभ, सामाजिक उत्थान, आदि वह सामाजिक क्षेत्र हैं, जिन पर नेहरू ने ध्यान केंद्रित किया और काम किया। अब हम इन पर चर्चा करते हैं:

शिक्षा: नेहरू भारत की शिक्षा व्यवस्था के प्रति एक महान दूरदर्शी थे। भारत की भावी प्रगति के लिए उन्होंने भारत के बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा को एक आवश्यकता मानते हुए उसकी वकालत की। उनके कार्यकाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences; AIIMS), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institutes of Technology; IITs), भारतीय प्रबंधन संस्थान (Indian Institutes of Management; IIMs), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institutes of Technology; NITs), और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (Indian Institute of Public Administration (IIPA), नई दिल्ली, के साथ–साथ उच्च शिक्षा के कई संस्थानों की स्थापना की गई।

कुछ ''पहले दर्जे के संस्थानों'' (First-rate Institutions) की द्वदंता और ''बिना किसी शिक्षा'' के संस्थानों (Institutions without any Education) की अधिकता से नेहरू परेशान थे। उन्होंने शैक्षिक स्वतंत्रता के बारे में लिखा और विदेशी अकादमिक सहयोग का समर्थन किया। साथ ही, विदेशी विशेषज्ञों के कई ''दूसरे दर्जे का सामान'' (Second-rate Stuff) को देखकर वह काफी विचलित रहते थे, और फिर विडंबना यह भी थी कि इन विशेषज्ञों को भारतीय समकक्षों की तुलना में अधिक भुगतान दिया जाता था। उन्होंने आवश्यकता अनुसार विशेष भर्ती चैनलों (Channels) के माध्यम से विदेश में प्रशिक्षित भारतीयों की अधिक प्रभावी तैनाती का सुझाव दिया (दास–Das, *op.cit.*)।

नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी की एक प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। इस काम के लिए उन्होंने सामूहिक ग्राम नामांकन कार्यक्रमों के निर्माण की देखरेख की और हजारों स्कूलों का निर्माण किया। उन्होंने बहुत से ऐसे पहल किए भी जैसे, कुपोशण से लड़ने के लिए बच्चों को मुफ्त दूध और भोजन देने का प्रावधान, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, और खासकर ग्रामीण इलाकों में वयस्कों के लिए आयोजित व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल (अग्रवाल–Agrawal, 2008)।

हिन्दू पर्सनल लॉ: नेहरू के नेतृत्व में संसद ने कानूनी अधिकारों को बढ़ाने और महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता के लिए हिंदू व्यक्तिगत कानून (Hindu Personal Law) में कई बदलाव किए। नेहरू के आग्रह पर अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जो यह वर्णन करता है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Law) सुरक्षित करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद ने भारत में धर्मनिरपेक्षता को आधार बनाया है (अरकेल–Erckel, 2011)।

सबसे महत्वपूर्ण, मुसलमानों को विवाह और वंषानुक्रम से संबंधित मामलों में उनके पर्सनल लॉ को बनाए रखने के लिए आजादी थी। जबकि नेहरू ने मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (Muslim Personal Law) को विधान कानूनो से अलग कर दिया था, उनकी सरकार ने 1954 में विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) को भी पारित किया। इस अधिनियम के पीछे भारत में सभी को व्यक्तिगत कानूनों के बाहर एक सिविल विवाह के तहत शादी करने की क्षमता देने का विचार था। इस अधिनियम ने बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित किया और यह भी कहा कि, संबंधित व्यक्तिगत कानूनों के बजाय, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित होगा।

नेहरू और आरक्षण नीति: सरकारी सेवाओं और शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सामाजिक विशमताओं को मिटाने और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए आरक्षण की एक प्रणाली बनाई गई थी। नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सद्भाव का भी समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बड़ा। उनके लिए शरणार्थी समस्या का समाधान पुनर्वास और पुनरूद्धार में निहित था, दान बांटने में नहीं। उन्होंने 'दलित' शब्द का प्रयोग अस्वीकार किया, क्योंकि वह मानते थे कि यह व्यक्ति को कलंकित करता है, और वे सभी सकारात्मक कार्रवाई के समर्थन में थे (दास–Das, *op.cit.*)।

नेहरूवाद और समाजवादी विचार: नेहरू को विश्वास था कि भारत समाजवाद के आधार पर आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकता है। वह समाजवाद की विचारधारा की ओर प्रतिबद्ध थे, लेकिन उनकी समाजवाद की अवधारणा मार्क्स और अन्य राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा

परिभाषित अवधारणा से काफी अलग थी। भारत की स्वतंत्रता से बहुत पहले, 1929 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) के लाहौर अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने घोषित किया कि वह एक समाजवादी और एक लोक-तंत्रवादी थे, और वह सामंती अभिजात वर्ग में विश्वास नहीं करते थे। उसी समय में, उनके समाजवाद के आदर्श ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी प्रभावित किया। ''मैं यह नहीं समझता कि क्यों समाजवाद के अंतर्गत व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का बहुत महत्व नहीं होना चाहिए; वास्तव में, वर्तमान व्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक स्वतंत्रता होती है। समाजवाद विवेक और मन की स्वतंत्रता, उद्यम की स्वतंत्रता और यहां तक कि, प्रतिबंधित पैमाने पर, निजी संपत्ति का अधिकार भी प्रदान कर सकता है'' (नेहरू, 1946, *op.cit.*)।

सोवियत संघ की नेहरू की यात्रा उनके दार्शनिक बनने और राजनीतिक विचारों में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने निर्णायक रूप से लोकतंत्रवाद की ओर रुख किया और वह समाजवादी आक्षेपों के प्रबल समर्थक बन गए। उन्होंने (*Ibid.*) समीक्षा की, कि ''जब तक निजी एकाधिकार बना रहेगा, समाज की किसी भी समाजवादी संरचना के लिए विकसित होना संभव नहीं है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि समाज उत्पादन के प्रमुख साधनों को नियंत्रित करे और इन एकाधिकार को विकसित होने से रोके''। यदि ''लोकतांत्रिक समाजवाद'' उनकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का वैचारिक मूल है, तो उन्होंने लोगों की सहमति के आधार पर, हठधर्मिता और हिंसा से वंचित और मजबूत नैतिक मूल्यों से बने हुए, एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की थी।

उनके नियोजन, सामुदायिक विकास, विकेंद्रीकरण, रोजगार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, धर्मनिरपेक्षता और समान अवसर पर विचार सामूहिक रूप से उस ''समतावादी भारत'' को प्रदर्शित करते हैं, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। वह समाज के अधिग्रहण (Acquisitiveness) के स्वरूप के आलोचक थे और इस तरह उन्हें रोकने में राज्य की भूमिका का समर्थन करते थे। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था की हर गाँव में एक पंचायत, एक सहकारी समिति, और एक स्कूल होना चाहिए (दास–Das, *op.cit.*)।

6.3.4 लोक प्रशासन पर नेहरू के विचार

देश के विकास के लिए कुछ नीतियां और उन्हें लागू करने के लिए संरचनाओं को बनाने के अतिरिक्त प्रशासन विज्ञान के अध्ययन और अनुप्रयोग में नेहरू का योगदान अपरिहार्य है। देश में प्रशासनिक सुधार लाने में उनकी बहुत रुचि थी।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA), नई दिल्ली, जिसके बनने के बाद से ही नेहरू उसके साथ अध्यक्ष के तौर पर जुड़े थे, देश में प्रशासनिक सुधार और विकास में नेहरू की रुचि का एक उदाहरण है। नेहरू ने इसके काम और विकास में बहुत रुचि ली। कुछ नीतियों को लागू करने की संरचना और उस संरचना को बनाए रखने के लिए कर्मियों की पसंद के रूप में नेहरू को श्रेय दिया जाता है।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक, डॉ होमी भाभा के नेतष्त्व में स्वायत्त परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission) की स्थापना में नेहरू ने सही संगठन का विकास किया। इसी तरह, उन्होंने प्रोफेसर महालनोबिस (Mahalnobis) (जिन्हें भारत में सांख्यिकीय विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है) को देश के सर्वोच्च सांख्यिकीय संस्थान को निर्देषित करने के लिए चुना अर्थात् भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (Indian Statistical Institute), कोलकता (उस समय कलकत्ता)। इन संगठनों के अतिरिक्त कई और, जिन्हें सरकारी नियंत्रण के साथ

स्वायत्तता प्रदान की गई थी, संगठन के नए पैटर्न थे, जिनके उद्भव के लिए नेहरू की सोच को श्रेय जाता हैं।

नेहरू ने इस बात की आशंका व्यक्त की कि शासन किस दिशा में कमजोर हैः भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विलंब, और बेईमान अधिकारियों और लोगों के बीच मिलाप। उनके लिए, सिविल सेवा तटस्थता एक कल्पना थी, हालाँकि उन्होंने नौकरशाहों को वस्तुनिष्ठ और अलग सोच विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह चाहते थे कि राज्य के गवर्नर अपनी भूमिका संवैधानिक ढांचे के भीतर सख्ती से निभाएं और खुद को ''श्रेष्ठ वर्ग'' न समझें (दास–Das, *op.cit.*)।

नेहरू भ्रष्टाचार के भी गंभीर आलोचक थे, जो समाज के साथ-साथ प्रशासन में व्याप्त हो गया था। नेहरू (1946, *op.cit.*) ने इशारा किया कि, सरकार अपने बेहतरीन इरादों के बावजूद सामान्य कर्मचारियों के मध्य भ्रष्टाचार की जाँच करने में असमर्थ हो गई है, और पुलिस और अन्य अधिकारियों को अपने आपको बचाने के लिए मदद दे रही है। यह तभी सफल हो सकता है, जब इसे भारतीय पुलिस का स्वैच्छिक समर्थन हो।

नेहरू सामुदायिक विकास और पंचायती राज कार्यक्रमों के पीछे एक प्रेरक शक्ति थे। हमें पता है कि कैसै त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान (Panchayati Raj Institutions, PRIs) विभिन्न राज्यों में शुरू किए गए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme, CDP) को 1952 में शुरू किया गया। नेहरू का मानना था कि ये कार्यक्रम प्रशासन को लोगों के पास लाने में मदद कर सकते हैं। इन्हें मीडिया के माध्यम से चुना गया था, जिसके माध्यम से जनता का हर सक्रिय सदस्य किसी न किसी रूप में समुदाय की कुछ भलाई करने के लिए तैयार किया जा सकता है।

नेहरू इन संस्थाओं को वास्तविक शक्तियाँ देकर उन्हें मजबूत करना चाहते थे। उनका विचार था कि इन संस्थानों की तुलना में अधिकारियों की भूमिका सलाहकार के स्वरूप में होनी चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि पंच और सरपंच को गलतियाँ करने की हद तक छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि वह सोचते थे कि ऐसी गलतियाँ उन्हें सीखने और उनकी तत्कालिक और दिन-प्रतिदिन की समस्याओं का ध्यान रखने में मदद करेगीं।

नेहरू (*Ibid.*) ने ठीक ही कहा था कि, ''पंचायत की गलतियाँ देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेंगी''। नेहरू के लिए, पंच एक प्रशासक भी होता है। पंचायत का हर सदस्य एक विशेष क्षेत्र का प्रशासक होता है, और उसे ऐसे ही पहचाना और सम्मान दिया जाना चाहिए। वह चाहते थे कि पंचायती राज संस्थान कायम रहें। उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा का समर्थन किया। उनके प्रधानमंत्री कार्य–काल के अंत के वर्षो में उन्होंने 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' के स्थान पर पॉल एपलबी (Paul Appleby) की परिभाषा 'लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण' का उपयोग करना पसंद किया।

6.3.5 रक्षा और विदेश नीतियों पर नेहरूवादी दृष्टिकोण

आज़ादी के पश्चात् नेहरू इंग्लैंड और अन्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने लंदन घोषणा (London Declaration) पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत भारत ने सहमति व्यक्त की जब वह जनवरी 1950 में एक गणतंत्र बन जाएगा तो वह राष्ट्रमंडल राष्ट्रों (Commonwealth of Nations) में शामिल होगा और ब्रिटिश सम्राट को उसके स्वतंत्र सदस्य राष्ट्रों के एक ''मुक्त संघ का प्रतीक और कॉमनवेल्थ के प्रमुख'' के रूप में स्वीकार करेगा।

हालांकि, नेहरू हर देश के साथ शांति और मैत्रीपूर्ण संबंधों में विश्वास करते थे, उन्होंने कश्मीर के संदर्भ में पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियों और वास्तविक अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने 1948 में हैदराबाद को और 1961 में गोवा को जब्त करने के लिए भारी सैन्य बल का भी प्रयोग किया। वह भूस्थैतिक (Geo–strategic) और 1947 में भारत की सैन्य ताकत और कमजोरियों के संदर्भ में काफी संवेदनशील थे।

नेहरू ने परमाणु हथियार के विकास की कल्पना की थी और 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। 1948 के शुरू से ही, अन्य दक्षिण एशियाई राष्ट्रों, विशेष रूप से पाकिस्तान, पर भारत की क्षेत्रीय श्रेष्ठता नीति के हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम को औद्योगिक राष्ट्रों के खिलाफ खड़े होने और परमाणु हथियारों की क्षमता को स्थापित और विकसित करने की नेहरू की उच्च महत्वाकांक्षा थी। उन्होंने परमाणु विस्फोट के मानव स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव के पहले अध्ययन की शुरुआत की, और उसे वह ''विनाश के भयानक इंजन (Frightful Engines of Destruction)'', के नाम से बुलाते थे, साथ ही उसके उन्मूलन के लिए लगातार अभियान भी चलाया।

नेहरू का सबसे बड़ा योगदान शीत युद्ध (Cold War) के दौरान गुटनिरपेक्षता की उनकी नीति थी। इसका मतलब था कि नेहरू को दोनों पावर ब्लॉक (अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ) से, शुरूआत से भारत के औद्योगिक आधार के निर्माण में, वित्तीय और तकनीकी सहायता मिली। इसका मतलब था कि भारत ने दोनों शक्तियों के प्रति तटस्थता बनाए रखी। सोवियत संघ और पश्चिम जर्मनी कि सहायता से बोकारो और राउरकेला में इस्पात मिल परिसर (Steel Mill Complexes) बनाए गए। उनके आदर्शवादी दृष्टिकोण ने भारत को गुटनिरपेक्षता में नेतृत्व की स्थिति प्रदान करने पर केंद्रित किया था, जिससे पर्याप्त औद्योगिक विकास हुआ। वास्तव में, 1950 से 1965 के बीच उद्योग में प्रति वर्श 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो लगभग तिगुना औद्योगिक उत्पादन था और इसने भारत को विश्व के सातवें सबसे बड़े औद्योगिक देश के रूप में स्थापित किया (वाल्श–Walsh, 2006)।

नेहरू को भारतीय विदेश नीति का एकमात्र निर्माता माना गया है। उन्होंने शीत युद्ध लड़ रहे दो शत्रुतापूर्ण महाशक्तियों के विरोध में एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के मध्य समर्थन बनाने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र के एक मजबूत समर्थक होने के नाते, तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का सुझाव देने वाली कश्मीर पर ग्राहम रिपोर्ट से नेहरू अचंभे में आ गए थे। इस पर ज़ोर देते हुए की देश की रक्षा हथियारों की तुलना में उसके मनोबल पर अधिक निर्भर है, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादास्पद मुद्दों को हल करने के पक्ष में तर्क दिया, विशेष रूप से सहयोग की भावना के साथ परस्पर लाभकारी विकास परियोजनाएँ उनमें प्रमुख हैं (दास–Das, *op.cit.*)।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नेहरू सैन्य कार्रवाई और सैन्य गठबंधनों के विरूद्ध थे। नेहरू ने संसद में जो भाषण दिए, वे दुनिया भर में समकालीन विकास के एक शानदार विश्लेषण और मूल्यांकन प्रदान करते हैं–चाहे वह श्रीलंका में तमिलों के प्रश्न हो या इंडोनेशिया में विदेशी हस्तक्षेप, वियतनाम और अल्जीरिया के उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष, (De-Stalinisation), या नेपाल में अस्थिरता का प्रश्न। उन्होंने सोवियत द्वारा परमाणु परीक्षण के निलंबन का स्वागत किया, लेकिन हंगरी में मास्को के हस्तक्षेप की निंदा की। वह दृढ़ता से भारत के अन्य देशों के आपसी विवादों में हस्तक्षेप करने के खिलाफ थे, विवादों की सहमति को छोड़कर (*Ibid.*)।

29 अप्रैल 1954 को, नेहरू ने चीन के साथ शांतिप्रिय सहअस्तित्व के पाँच सिद्धांतों (Five Principles of Peaceful Coexistence) पर हस्ताक्षर किए, जिसे भारत में भारत-चीन सीमा समझौते के आधार के रूप में पंचशील के नाम से जाना जाता है। बाद के वर्षों में, उनकी विदेश नीति को सीमा विवाद पर बढ़ती चीनी दृढ़ता का सामना करना पड़ा। तिब्बत से 14वें दलाई लामा को शरण देने के उनके फैसले और उस पर चीन की झुंझलाहट के परिणामस्वरूप 1962 में भारत-चीन युद्ध हुआ। चीन के साथ युद्ध एक क्रांतिकारी बदलाव का कारण बना। उसके बाद नेहरू और अधिक यथार्थवादी अधिक रक्षा-उन्मुख बन गए (गांगुली और परदेसी–Ganguly and Pardesi, 2009)।

बोध प्रश्न-1

नोट : i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. नेहरूवादी दृष्टिकोण की विचारधारा और नीति के स्वरूप का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. नेहरू की आर्थिक और सामाजिक नीतियों की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

3. नेहरू की रक्षा और विदेश नीतियों पर एक नोट लिखिए।

.....

.....

.....

.....

6.4 निष्कर्ष

हालांकि नेहरू ने देश की बुनियादी नीतियों और उन्हें लागू करने के लिए संरचनाओं, और प्रशासन के सिद्धांतों को निर्धारित करने का प्रयास किया, वह प्रशासन की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन–जिन्हें वह स्वतंत्रता के बाद की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक मानते थे– करने में असमर्थ रहे। नेहरू सरकार ने न केवल इंपीरियल सर्विस (Imperial Service) के विशेषाधिकार को बनाए रखा, बल्कि एक संवैधानिक प्रावधान के साथ उन्हें

गारंटी भी प्रदान की। हालांकि जैसा कि उन्होंने खुद (1946, *op.cit.*) स्वीकार किया था, ''वे शायद ही लोकतांत्रिक ढांचे में उचित बैठती हैं और वे वर्ग विभाजन की भावना पैदा करती हैं, जो हमारी सभी सामाजिक संरचना का आधार हैं''।

भारत की प्रशासनिक प्रणाली में बदलाव के लिए पॉल एपलेबी (Paul Appleby) की सिफारिशों की प्रशंसा करने के बावजूद, नेहरू पर्याप्त बदलाव लाने के लिए बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं रह सकें। नई सेवा संरचना, जिसे अस्तित्व में लाया गया था, सिविल सेवा संरचना के बाच समान औपनिवेशिक प्रकार के कठोर वर्ग विभाजन को प्रतिबिंबित करती रही। इस प्रकार, नेहरू ने अपनी सोच और व्यक्तिगत समर्पण और लक्ष्यों को सर्वोच्च रखा, भले ही वह इसे अक्षरशः व्यवहार में नहीं ला सकें। एक बेहतर भारत के निर्माण में यह शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। इतिहास में उन्हें एक उत्कृष्ट राजनेता और राजनीतिज्ञ के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय विकास के लिए अपने जीवन की भावुक खोजों और विशाल प्रयत्नों को समर्पित कर दिया। उन्हें एक बहुआयामी व्यक्तित्व माना जाता है–लोकतांत्रिक एकीकरण और समाजवाद की प्रवृत्ति वाले एक राजनीतिज्ञ, अंतरराष्ट्रीयता और मित्रता के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले एक करिश्माई नेता, अलग दृष्टिकोण वाले एक लेखक, समकालीन घटनाओं के बारे में एक विचारक और जनता के नेता थे। इस इकाई ने उनके कुछ विचारों और धारणाओं को विस्तार से समझाया है।

6.5 शब्दावली

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) : अक्टूबर 1952 में, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। एक साथ पचपन सामुदायिक परियोजनाएं शुरू की गईं थीं। पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में इस कार्यक्रम का विस्तार व्यापक क्षेत्रों में किया गया। भारत में हर तीन गाँव में से लगभग एक को इस कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र के भीतर लाया गया था।

फैबियन समाजवाद (Fabian Socialism) : 1895 में फैबियन संस्था ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (London School of Economics and Political Science) को स्थापित किया। यह एक ब्रिटिश समाजवादी संगठन है, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी तख्ता–पलट के बजाय, क्रमिकतावादी और लोकतंत्र में सुधारवादी प्रयासों के माध्यम से लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना है। फेबियन संस्था का वर्ष 1900 में, श्रम प्रतिनिधि समिति के संस्थापक संगठनों पर और लेबर पार्टी जो इसमें से निकली थी इनपर बहुत प्रभाव था। ब्रिटिश राजनीति पर भी इसने शक्तिशाली प्रभाव छोड़ा था। फैबियन संस्था के अन्य सदस्य उन देशों से, जो पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, राजनीतिक नेताओं को शामिल करता है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के हिस्से के रूप में फैबियन सिद्धांतों को अपनाया।

हरित कांति (Green Revolution) : यह उस अवधि से संबधित है, जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण– जैसे अधिक उपज वाली किस्मों (HYV बीज) का प्रयोग, श्रृतु–आरोधी गेहूं के तने, ट्रैक्टर, सिंचाई की सुविधा, कीटनाशक, और उर्वरक को एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित किया गया था। भारत में यह कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में 1965 में हरित कांति शुरू हुई और इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इसने भारत को विदेशी निर्यात पर निर्भरता के बजाय अपने देश में आवश्यक फसलों का उत्पादन करने में स्वतंत्र बनाया। हालांकि, कई सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा सोचते हैं कि, इसने पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए समाजशास्त्रीय और वित्तीय समस्याओं को जन्म दिया और रासायनिक उर्वरकों और नकदी फसलों पर अत्यधिक निर्भरता पैदा की।

हिन्दू व्यक्तिगत कानून (Hindu Personal Law) : कानून सर्वात्रिक व पर्सनल होते हैं। यहाँ हम हिन्दू पर्सनल या व्यक्तिगत नियम की बात कर रहे है। हिन्दू कानून उन कानूनों का संग्रह है, जिन्हें बिट्रिश शासन में हिन्दू, बुद्ध, जैन, और सिख पर लागू किया गया। यह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा शासित है। हिंदू कानून के तहत निर्वसीयत और वसीयती उत्तराधिकारी संशोधन और विनियमित करने के लिए, निर्वसीयत (अनिर्दिष्ट संपत्ति) संबंधित, भारत की संसद द्वारा पारित एक संहिताबद्ध कानून है। लेकिन कुछ मामलों में, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम एक प्रमुख भूमिका निभाता है। पहले, महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता था और उन्हें संपत्ति में समान अधिकार नहीं थे। हिंदू कानून में विभिन्न कार्य और प्रावधान हैं, जो तलाक, विवाह, संपत्ति, अल्पमत पुत्र का अधिकार, पवित्र दायित्व, आदि जैसे मामलों में इसे नियंत्रित करता हैं, जो हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955; भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925; और संरक्षकता और दत्तक ग्रहण ऐक्ट, 1956 द्वारा शासित है। हिंदू कानून के मुख्य स्रोत रीति–रिवाज और कानून है, जहां से कानून की व्युत्पत्ति हुई है।

विचारधारा (Ideology) : विचारधारा आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मूल्यों और लक्ष्यों से संबंधित विचारों का एक निकाय होती है।

नेहरूवाद (Nehruism) : भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, के न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को सम्मिलित करती राजनीतिक विचारधारा को नेहरूवाद का नाम दिया गया है।

पंचशील (Panchsheel) : यह संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांत है। ये सिद्धांत हैं पारस्परिक सम्मान, गैर–अतिक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता, शांतिपूर्ण–सहस्तित्व।

6.6 संदर्भ लेख

Agrawal, M.G. (2008). *Freedom Fighters of India.* New Delhi, India: Isha Books.

Das, S. (26th July, 2011). Nehru's Vision of New India. *The Hindu.*

Erckel, S. (2011). *India and the European Union.* GRIN Verlag.

Ganguly, S. &Pardesi, M. (2009). Explaining Sixty Years of India's Foreign Policy. *India Review.*8(1), 4-19.

Khosla, M. (2015). *Letters for a Nation; From Jawaharlal Nehru to his Chief Ministers1947-1963.* U.K: Penguin.

Nehru, J. (1946). *The Discovery of India.* Calcutta, India: Signet Press.

Parekh, B. (1991). Nehru and the National Philosophy of India. *Economic and Political Weekly.* 26-1(2).

Sapru, R.K. (2015). *Development Administration.* Delhi, India: PHI Learning.

Sapru, R.K. (2017). *Administrative Theories and Management Thought*. Delhi, India: PHI Learning.

Yergin, D. & Stanislaw. (2002). *The Commanding Heights: The Battle for the World Economy.* New York, USA: Simon and Schuster.

6.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न-1

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:**

   - जवाहरलाल नेहरू को 'दूरदर्शी' नेता माना जाता है, जिन्होंने कल्पना और ज्ञान के साथ भारत के भविष्य के बारे में सोचा या उसकी योजना बनाई।
   - 'नेहरूवाद' परिभाषा का अर्थ जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थित एक दर्शन या विचारधारा है।
   - राजनीतिक रूप से, 'नेहरूवाद' का अर्थ 'धर्मनिरपेक्षता', 'वैज्ञानिक स्वभाव' और 'समावेशी उदारवाद' के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता है।
   - आर्थिक दृष्टि से, 'नेहरूवाद' का अर्थ 'देश की अर्थव्यवस्था' की दिशा निर्धारण और 'नियोजित विकास' में सक्रिय 'राज्य हस्तक्षेप' का प्रतीक है।
   - सरल शब्दों में 'विचारधारा' का अर्थ ''आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मूल्यों और लक्ष्यों से संबंधित विचारों का एक निकाय है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियात्मक कार्यक्रम को सकारात्मक करता है''।

- 'विचारधारा' परिभाषा और विश्वास की एक श्रेणी है, जो एक विशेष संस्कृति का चित्रण करती है।
- ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोष 'विचारधारा' को 'कल्पना या ज्ञान से भविष्य की योजना या उसे सोचने की क्षमता' के रूप में परिभाषित करता है।
- इसका अर्थ होता है, भविष्य क्या होगा और कैसा हो सकता है; उसकी एक मानसिक छवि।

2. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिएः**

- तेजी से औद्योगिकीकरण
- मिश्रित अर्थव्यवस्था
- लोक क्षेत्र के लिए प्राथमिकता
- लोक क्षेत्र को स्वायत्तता
- कम नौकरशाही
- स्वीय विधि, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार
- समतावाद और गैर-भेदभाव
- समाजवादी विचार का अनुमोदन करना

3. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिएः**

- नेहरू ने हैदराबाद को 1948 में और गोवा को 1961 में अधिग्रहित करने के लिए भारी सैन्य बल का प्रयोग किया।
- वह गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास करते थे।
- नेहरू ने शीत युद्ध लड़ रहे दो शत्रुतापूर्ण महाशक्तियों के विरोध में नव–स्वतंत्रता प्राप्त एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों से समर्थन बनाने की मांग की।
- संयुक्त राष्ट्र के कश्मीर में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का प्रस्ताव नेहरू द्वारा पसंद नहीं किया गया था।
- उन्होंने सोवियत द्वारा परमाणु परीक्षण के निलंबन का स्वागत किया, लेकिन हंगरी में मास्को के हस्तक्षेप की निंदा की।
- वह अन्य देशों के बीच विवादों में भारत के हस्तक्षेप करने के दृढ़ता से खिलाफ थे।
- दलाई लामा को शरण देने की उनकी नीति तीखी आलोचना में आई।
- 1962 में चीन के साथ युद्ध एक क्रांतिकारी बदलाव का कारण बना। उसके बाद नेहरू और अधिक यथार्थवादी अधिक रक्षा-उन्मुख बन गए।

इकाई 7 : उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में नीति*

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 उदारीकरण के संदर्भ में नीति

7.3 निजीकरण के संदर्भ में नीति

7.4 वैश्वीकरण के संदर्भ में नीति

7.5 निष्कर्ष

7.6 शब्दावली

7.7 संदर्भ लेख

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बाते समझ सकेंगेः

- 'उदारीकरण', 'निजीकरण' और 'वैश्वीकरण' का अर्थ और महत्व;
- राष्ट्रीय नीति कार्यसूची पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव; तथा
- विश्व आर्थिक पुनर्गठन की बाधाओं का परीक्षण।

7.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय नीति कार्यसूची को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एल.पी.जी.–LPG संक्षिप्त रूप में) की लहरों और बलों द्वारा आकार दिया जा रहा है, और इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है कि समाज में घटनाएं होती रहती है। जैसा कि हम इन लहरों का हिस्सा हैं, हम सांस्कृतिक मूल्यों में गहरी राष्ट्रव्यापी सामाजिक उथल–पुथल और अशांति का भी अनुभव करते है। शायद, इसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे उदारवादी लोकतांत्रिक समाज समान मुद्दों का सामना करते हैः अपराध, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, हथियारों की दौड़, बीमारियों और बढ़ती जनसंख्या के कारण संबधी खतरों का फैलाव।

यहां, इसलिए, इधर–उधर बिखरने (Spillover) के बीच एक तनाव है, जिसे वैश्विक स्तर पर घटित होना और राष्ट्रीय प्रभुता के संरक्षण की वास्तविकता कहा जा सकता है। इसका तर्क यह है कि राष्ट्रीय नीति कार्यसूचियों को एल पी जी (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) की घटनाओं के मद्देनजर व्यापक रूप से आकार और

*योगदान : डा. आर. के. सप्रू, प्रोफेसर, लोक प्रशासन (सेवानिवृत), पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

सूत्रबद्ध किया जा रहा है। यह इकाई एल पी जी के स्वरूप और नीति कार्यसूची पर इसके प्रभाव की चर्चा करेगी।

7.2 उदारीकरण के संदर्भ में नीति

नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर पर बनती है, लेकिन एल पी जी के संदर्भ में ये विश्व स्तर पर शासित होती हैं। नई आर्थिक नीति से पहले (1991), केन्द्र सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई नियंत्रण लगाए थे जैसे– औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, मूल्य नियंत्रण, आयात प्रतिबंध, विदेशी विनिमय नियंत्रण आदि। इसने नए उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों के उत्साह को कम कर दिया और भ्रष्टाचार, अनुचित विलंब, अक्षमता और प्रभाव–शून्यता को जन्म दिया। नई आर्थिक नीति (New Economic Policy-NEP) 1991 में इस धारणा के साथ नीतिगत उपाय के रूप में शुरू की गई थी कि बाजार शक्तियाँ अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रण की अपेक्षा अधिक प्रभावी तरीकें से निर्देशित कर सकती है।

उदारीकृत नीति की महत्वपूर्ण भूमिका सरकारी नियंत्रणों को आसान बनाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। उदारीकरण को एक विधि के रूप में माना जाता है कि कैसे राज्य कुछ निजी व्यक्तिगत व्यापार पर सीमाएं बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है कि इन सीमाओं को समाप्त करना और अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों को खोलना। 1991 में भारत में उदारीकृत नीति के शुभारंभ के साथ, सरकार ने निजी क्षेत्र के संगठनों को कम प्रतिबंधों के साथ व्यावसयिक संगठनों का संचालन करने के लिए विनियमित किया। विकासशील देशों के लिए, उदारीकरण ने विदेशी कंपनियों और निवेशों के लिए आर्थिक सीमाएँ खोल दी हैं। उदारीकरण का उद्देश्य उन प्रतिबंधों को समाप्त करना था, जो अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि में बाधक बने। सरकारी नियंत्रण को शिथिल करना या विभिन्न व्यापार मामलों और उद्योगों पर सरकारी प्रतिबंधों को कम करना एक उदार नीति को दर्शाता है।

उदारीकरण नीति के उद्देश्य

उदारीकरण नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैः

- घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना;
- नियमित आयात और निर्यात के साथ अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना;
- विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को बढ़ाना;
- देश के वैश्विक बाजार सीमाओं का विस्तार करना; और
- देश के कर्ज के बोझ को कम करने का प्रयास करना।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को क्षमताओं के साथ विश्व की सबसे तेज़ विकासशील अर्थव्यवस्था बनाना था, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ मिलाने में सहायता मिले। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, उदारीकरण नीतियों में सरकारी संस्थानों और परिसंपत्तियों का आंशिक या पूर्ण निजीकरण, अधिक श्रम पूंजी पर कम प्रतिबंध, खुले बाजार इत्यादि शामिल हैं।

7.3 निजीकरण के संदर्भ में नीति

देश की अर्थव्यवस्था की संवृद्वि के प्रति निजी क्षेत्र के महत्व और योगदान की उपेक्षा करना गलती होगी। लोक नीति में लक्ष्यों और उद्देश्यों का व्यापक विस्तार सम्मिलित है। इसमें लोक कार्यों को करने के लिए निजी संगठनों को संचालित करने वाली नीति शामिल होती है। विभिन्न कानूनों और नीतियों के तहत निजी संगठन अस्तित्व में आते है। सरकारी कंपनियों को दो तरीकों से निजी कंपनियों में बदला जा सकता है;

i) विनिवेश द्वारा;

ii) लोक क्षेत्र की कंपनियों के सरकारी स्वामित्व और प्रबंधन की वापसी के द्वारा।

जब उत्पादक संपत्तियों का 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो अधिनियम को विराष्ट्रीयकरण (Denationalisation) कहा जाता है। जब निजी क्षेत्र का स्वामित्व 50 प्रतिशत से अधिक का होता है, लेकिन शेयरों के हस्तांतरण के द्वारा पहले से अनुमानित लोक क्षेत्र की कपंनी के 100 प्रतिशत से कम का स्वामित्व होता है, तो इसे आंशिक निजीकरण कहा जाता है। यहां निजी क्षेत्र अधिकांश हिस्सों का मालिक है। इसलिए, निजी क्षेत्र के पास कंपनी की कार्य पद्धति और स्वतंत्रता पर पर्याप्त नियंत्रण है। केन्द्र सरकार ने 2020 में एयर इंडिया (लोक क्षेत्र का उद्यम) को निजी क्षेत्र को सौंपने का फैसला किया है।

निजीकरण और नए लोक क्षेत्र प्रबंधन तकनीकों के प्रति परिवर्तन के एक अध्ययन में, मार्टिन (Martin, 1993) ने तर्क दिया है कि ''राष्ट्रीय नीति कार्यसूचियों को वैश्विक आर्थिक पुनर्गठन की शक्तियों द्वारा आकार दिया जा रहा हैः राज्य की भूमिकाओं की परिभाषा में, अतंर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताओं के कारण निजीकरण और लोक क्षेत्र व्यावसायीकरण के वैश्विक संचालन द्वारा लोक हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने के कार्य को कम करके दूर किया जा रहा है... निजीकरण को वैश्विक' स्तर पर संचालन के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों के स्थानान्तरण द्वारा संचालित किया जा रहा है। संघटित विश्व अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया में दूरसंचार, वित्त और ऊर्जा जैसे उद्योगों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इन उद्योगों की वैश्विक संरचना निजीकरण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी की मांग करती है।''

नौकरशाही में स्वयं–हित दृष्टिकोण को देखते हुए, गॉर्डन टूलॉक (Gordon Tullock) ने अपनी किताब 'द पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी (The Politics of Bureaucracy, 1965) में बाहर से काम करने का ठेका देने और निजीकरण के द्वारा नौकरशाही के अंदर प्रतिस्पर्धा शुरू करने की सिफारिश की और प्रर्दशन को पुरस्कृत करके सरकारी विभागों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया। अपनी 1976 आई ई ए पैम्फलेट (I E A Pamphlet) में उन्होंने जो विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत किए, वे 1970 के दशक में बहुत अधिक प्रभाव नही डाला, लेकिन 1980 और 1990 के दशक में वे पूरी तरह से उभर के उपर आए। (देखेः पीटर सेल्फ–Peter Self, 1993)।

सरकार को फिर से संगठित करने की आवश्यकता अनुभव करने वाले समर्थकों ने तर्क दिया है कि प्रबंधकीय परिवर्तनों में अधिक बाजार संचालित विकेन्द्रीकरण नीति प्रक्रिया शामिल है, जिसमें अधिक जटिल समाज का प्रबंधन करने के लिए पदानुक्रम से भागीदारी और सम्मिलित काम (Team Work) तक एक परिवर्तन है (ओसबोर्न और गैबलर–Osborne and Gaebler,

1993)। हालाँकि, सरकार, क्षेत्रों और साधनों की इस पुनः मिलान (Remixing) को अधिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जटिलता और वित्तीय बाधाओं की स्थितियों में नियंत्रण (और वैधता) बनाए रखने के लिए सरकार की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उपायों के रूप में भी देखा जा सकता है।

लोक–क्षेत्र प्रबंधन की प्रवृत्तियों के सबसे व्यापक सर्वेक्षणों में से एक ओ ई सी डी (OECD) (1993) ने सूचना दी कि सदस्य देशों के बीच सबसे लोकप्रिय पहलों में शामिल है:

- केन्द्रीय सरकार का विघटन;
- 'एजेंसियों' का विकास;
- लोक उद्योगों को पुनर्गठन;
- लोक क्षेत्र के लिए सीमाएं;
- निजीकरण;
- विकेन्द्रीकरण;
- केन्द्रीय प्रबंधन निकायों की नई भूमिका; और
- बाजार–जैसे तंत्र।

इस प्रकार, पूरे ओ ई सी डी (OECD) देशों में, नीतियों के सर्वांग कवच (Panoply) की तस्वीर इस प्रकार बनाई गई है कि निजी क्षेत्र का अनुसरण लोक क्षेत्र करे और नागरिकों के समीप लोक सेवाओं का वितरण किया जाए (ओ ई सी डी–OECD सर्वेक्षण, 1993)।

निजीकरण नीति के उद्देश्य

निजीकरण के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है:

- सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारना;
- लोक क्षेत्र की कपंनियों के कार्यभार को कम करना;
- विनिवेश से धन बढ़ाना;
- सरकारी संगठनों की दक्षता में वृद्धि करना;
- उपभोक्ता को बेहतर और अच्छी वस्तुए और सेवाएं प्रदान करना;
- समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना, तथा
- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment) को प्रोत्साहित करना।

इस प्रकार, निजीकरण का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

बोध प्रश्न 1

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. उदारीकरण के संदर्भ में नीति के स्वरूप पर चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. निजीकरण के संदर्भ में नीति के स्वरूप पर चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

7.4 वैश्वीकरण के संदर्भ मे नीति

'उदारीकरण' और 'निजीकरण' जैसे शब्दों की तरह 'वैश्वीकरण' भी दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया है। हालांकि, इस शब्द ने दुनिया भर में विभिन्न वैचारिक, बौद्धिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। लेकिन वैश्वीकरण और इसके प्रभाव ने राष्ट्रीय नीति कार्यसूचियों को आकार दिया है। कुछ विद्वानों ने व्यक्त किया है कि वैश्वीकरण ने राज्य और प्रशासन को समाप्त कर दिया है (स्टीवर–Stever, 1988)।

वैश्वीकरण का अर्थ

'वैश्वीकरण' कोई क्षेत्रीय सीमाओं को नही पहचानता और दुनिया के संपूर्ण क्षेत्र का दावा करता है। यह विश्व शक्तियों, आर्थिक प्रणालियों और प्रशासनिक कार्यों के एकीकरण और अभिसरण को दर्शाता है। वैश्वीकरण को कई विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया है, क्योंकि वे इसे विभिन्न संदर्भों में देखते हैं। अर्थशास्त्रियों के लिए, वैश्वीकरण पूरी तरह से एकीकृत विश्व बाजार की दिशा में एक उन्नत कदम है। राजनीतिक वैज्ञानिक वैश्वीकरण को अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शासी निकायों के साथ एक नई विश्व व्यवस्था के रूप में देखते है, अर्थात् विचार करते हैं। व्यावसायिक विद्वान इसे सीमा रहित दुनिया में असीमित अवसरों के रूप में देखते है। अन्य लोग वैश्वीकरण को केवल निजी क्षेत्र के निगमों द्वारा संचालित एक घटना के रूप में देखते है, न कि सरकारों के द्वारा संचालित घटना के रूप में। आमतौर पर, वैश्वीकरण को देशों के बीच बाधाओं को कम करने और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संपर्क को समीप लाने के लिए प्रोत्साहन कर्ता के रूप में देखा जाता है, जो जीवन स्तर के बारे में ज्ञान साझा करने के लिए प्रत्येक स्थान पर लोगों की क्षमता में अत्यंत वृद्वि कर सकता है। वैश्वीकरण वैश्विक बाजार है। संक्षेप में, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो नकारात्मक के साथ–साथ सकारात्मक परिणामों पर भी जोर देती है।

राष्ट्रीय नीति कार्यसूची पर वैश्विक घटनाओं का प्रभाव

विकासशील देश विशेष रूप से वैश्विक स्पर्धाओं कार्यों के लिए कमजोर हैं और वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर बहुत अधिक निर्भर है। परिणामस्वरूप,

राष्ट्रीय नीतियां वैश्विक मुद्दों के साथ गूंथ जाती है अर्थात आपस में मिल जाती है। ''क्योंकि गरीब देशों की सामान्य रूप से दुर्बल राजनीति और कुछ स्वायत्त संस्थानों के साथ जवाबदेही की कमजोर व्यवस्थाएँ होती हैं, जिस कारण उन पर विशेष प्रभाव डालने का प्रयास किया जाता है'' (विश्व बैंक–World Bank, 1992)। राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएँ अब बाहर के दबावों और प्रभावों के लिए अभेध नहीं है। लोक नीति अब एक विश्व प्रणाली के साथ– साथ राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणातियों में भी होती है। परस्पर निर्भरता के बढ़ते संबंधों के परिणामस्वरूप दुनिया एकल सामाजिक व्यवस्था बन गई है। मुद्दा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और राष्ट्रीय और विश्व अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक नए प्रकार का परस्पर संबंध है। एंथनी गिंडेस (Anthony Giddens, 2007) ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निगम, बढ़ता आर्थिक एकीकरण, और संचार और मीडिया का वैश्वीकरण ऐसे प्रमुख कारक है, जो वैश्विकता के लिए बनाए जाते है। एक देश में नीति निर्माताओं का अनुसरण करने का प्रयास करना, अब वैश्विक पर्यावरण का हिस्सा बन गया है।

वैश्वीकरण के साथ राष्ट्र राज्य और अन्य देशों के बीच पारस्परिक विचार–विमर्श का एक बड़ा कार्य क्षेत्र है। एक राष्ट्र राज्य नीति कार्य सूची पर अब कम नियंत्रण का उपयोग करने लगा क्योंकि यह 20वीं शताब्दी की दूसरी छमाही (Half) में था। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, इसका अर्थ यह है कि नीति एजेंडा वैश्विक हो सकता है, लेकिन नीति निर्माण और कार्यान्वयन राष्ट्रीय रहता है। इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और राष्ट्रीय और विश्व अर्थव्यवस्था के बीच एक नए प्रकार का परस्पर संबंध है।

वैश्विक राजनीति ने राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण में, विशेष रूप से विकासशील राष्ट्रों की नीतियों के निर्धारण में विशेष भूमिका निभाई है। वैश्विक मुद्दों के साथ सहभागिता है अर्थात् एक दूसरे परस्पर प्रभाव डालते है, जो बदले में स्थानीय स्तर के मुद्दों को परस्पर प्रभावित करते हैं। वैश्वीकरण का मानना है कि यह बदलाव हमेशा के लिए परस्पर संवादात्मक और पारगम्य बनते जा रहे है, और जिससे एक नई नीति बन रही है। अधिकांश विकासशील देशों ने 1980 के दशक और 1990 के दशक के दौरान अपनी व्यापार व्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण उदारीकरण को बढ़ावा दिया, सीमा–शुल्क को बहुत कम किया और विश्व बैंक तथा यूरोपीय देशों के दबाव के तहत लोक उद्यमों के व्यापार और निजीकरण के लिए गैर–शुल्क बाधाओ को दूर किया।

वैश्वीकरणः राष्ट्रीय नीति कार्यसूची के लिए तात्पर्य

आज, दुनिया वैश्वीकरण के उच्च स्तर और इसके प्रभाव का सामना कर रही है। वैश्वीकरण ने समाज के साथ ही राजनीति को भी बदल दिया है। वास्तव में, जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, वैश्वीकरण के कई परिणाम होते है, समाजों और उनका शासन प्रणालियों के लिए दोनों सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हैं। ये प्रभाव सभी देशों में समान रूप से वितरित नहीं होतें, और अब तक विकसित राष्ट्र प्रमुख लाभार्थी हैं, जबकि विकासशील राष्ट्र इसके लाभों के सीमांत प्राप्तकर्त्ता है।

दूसरा, राज्य के कार्यों के दृष्टिकोण में बदलाव है। ट्रासंवर्ल्ड निगमों (Transworld Corporation) द्वारा शासित बाजार–संचालित और निगम–राज्य के लिए राज्य और लोक प्रशासन विचलन का वैश्विक रूपांतर है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि बाजार–संचालित राज्य अनिवार्य है और यह निगम पूंजीवाद के हितों की सेवा करने की ओर अभिमुख होता है।

तीसरा, यह तर्क दिया जाता है कि वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता, लोकतंत्र और अधिकांश विकासशील देशों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। अंतराष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), साथ ही साथ महाशक्तियों के प्रभुत्व वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मेजबान–संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय, और ट्रांसवर्ल्ड निगम वैश्वीकरण के निर्णयों को अपनाने के लिए दबाव डालने वाले ऐसे राज्य सदस्य है, जो राष्ट्रीय हितों के विरूद्व भी जा सकते है। वैश्विक युग में, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर समानता एक मौलिक मुद्दा है। मुख्य रूप से वैश्वीकरण महाशक्तियों के हितों की सेवा से गरीबी और अविकसितता की समस्याएँ उत्पन्न होती है।

चौथा, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, वैश्वीकरण को पारिस्थितिक प्रणाली के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। अधिकांश विकासशील और विकसित राष्ट्र प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत कम ध्यान देते है। हाल के दशकों में ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) की दर बहुत अधिक रहीं है। इसके परिणामस्वरूप, महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि हुई हैं, ग्लेशियरों (Glaciers) में गिरावट आई है और हिमपात अधिक हुए है। पिछले 50 वर्षों में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साउड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड (Carbondioxide, Methane and Nitrous Oxide) मुख्य रूप से कृषि के कारण हैं।

पाँचवा, हेनकॉक (Hankock,1988) ने महाशक्तिशाली राष्ट्रों और ट्रांसवर्ल्ड निगमों को 'गरीबी का स्वामी' नाम दिया है। वैश्वीकरण गरीबी और असमानता दुनिया भर में है। यह तकनीकी नवाचारों के माध्यम से अधिक बेरोजगारी, कर सब्सिडी और कर व्यय के साथ प्रणाली को संचालित करने वाला और उसे खाली करने का कारण बनता है, और पुलिस तथा सामाजिक नियंत्रण के लिए सुरक्षा और सैन्य कार्यों पर बड़े पैमाने पर व्यय की मांग करता है। इसका परिणाम घर और दुनिया भर में शासन और लोक प्रशासन और अंततः सामाजिक क्रांतियों में बढ़ता संकट है। (ली फेबर–Le Feber, 1984)

फारज़मंद (Farazmand, 2007) ने तर्क दिया है कि वैश्वीकरण कम की अपेक्षा अधिक युद्व का फैलाव करेगा, क्योंकि वैश्वीकरण बल और संस्थान नियमित वैश्वीकरण के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए हिंसा का उपयोग करेंगे। दूसरी ओर गिडेंस (Giddens) का दावा है कि वैश्विक युग में, शांति और सुरक्षा राष्ट्रों के सहयोग पर निर्भर करती है, साथ ही मान्यता है कि कोई भी राष्ट्र, तथापि शक्तिशाली नहीं है, फिर भी वह अकेला समस्याओं का सामना कर सकता है। उन्होनें देखा हैः ''महानगरीय राष्ट्रों का निर्माण– एक समग्र पहचान के साथ, लेकिन उनकी विविधता में प्रसन्नता– एक मुख्य साधन है, जिसमें एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची ज़ारी हो सकती है और उसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

बोध प्रश्न 2

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपना उत्तर मिलाइए।

1. राष्ट्रीय नीति कार्यसूची पर वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए।

.....

.....

.....

.....

7.5 निष्कर्ष

यह व्यापक रूप से महसूस किया जाता है कि विकासशील लोकतांत्रिक देशों में, नीति कार्यसूची वैश्विक ताकतों द्वारा संचालित होती है। समस्याएं एक ऐसे संदर्भ में उत्पन्न होती हैं, जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां विचारों और राजनीतिक रणनीतियों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, नियोजन मॉडल के साथ बंधी हुई अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि, ठहराव, या और भी बुरे परिणामों का अनुभव किया। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का पतन था लेकिन नियोजन ताबूत में अंतिम कील (The final nail in the planning coffin) के मुहावरे के समान था। 1990 के दशक से, दुनिया भर के देश लोक उद्यमों के निजीकरण में सक्रिय रूप से लगे हुए है। हांलाकि, निर्णय या नीति की शक्ति और इसे लागू करने की क्षमता बड़े पैमाने पर राष्ट्र राज्यों के भीतर बनी हुई है। इसलिए उधल–पुथल (Spillover) प्रभाव जो वैश्विक स्तर पर हो रहा है, राष्ट्रीय संप्रभुता के संरक्षण की वास्तविकता के बीच एक तनाव है। वैश्विक कार्यसूची के दबाव के विपरित, यह तथ्य बना हुआ है कि संकट के समय ''सरकारें परस्पर सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय नीति–निर्माण से पीछे हटने की अपेक्षा समीप सहभागिता के अंदर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होती है।'' वैश्विक संदर्भ में आम मुद्दों और समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शीघ्रता से पहचाना जा सकता है, लेकिन निर्णय लेने और कार्यान्वयन अभी भी बड़े पैमाने पर राष्ट्र राज्यों के भीतर ही हैं। वैश्विक सामाजिक– आर्थिक फ्रेमवर्क राष्ट्र राज्यों की सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली राजनीतिक प्रक्रियाओं और नीतियों को परस्पर प्रभावित करता है। वैश्विक नीति मामलों के सम्मेलन के होते हुए भी नीति प्रर्दशन में राष्ट्र राज्यों की सफलता भिन्न हो जाएगी।

हालांकि, कुछ समय के लिए, दुनिया भर में वैश्वीकरण के पतन का आभास हो सकता है। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की वापसी यह संकेत देती है कि 'वैश्वीकरण' के युग में कुछ गलत है। अब, यह महसूस किया गया है कि अधिकांश देश अपनी मौद्रिक, राजकोषीय, आप्रवासन और श्रम नीतियों में स्वतंत्र रहना चाहते है। फिर भी, यह वास्तव में संयुक्त विश्व या वैश्वीकृत विश्व है। विश्व के एक भाग में जो घटित होता है, वह दूसरे को प्रभावित करता है। यू एस या यू के (US or UK) की विदेश, रक्षा और आर्थिक नीतियां भारत में नीतियों को प्रभावित करने के लिए बाध्य है। कोविड 19 प्रकरण और एक के बाद एक राष्ट्र राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) यह दर्शाता है कि एल पी जी अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में नीति कभी भी आसपास की घटनाओं से अप्रभावित नहीं रह सकती। कोरोना वायरस के भय से सभी राष्ट्रों को अन्य राष्ट्रों द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों का परस्पर प्रभाव और अनुसरण करते हुए देखा गया है। इस इकाई में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के स्वरूप पर विचार– विमर्श किया गया है। इस इकाई में विभिन्न देशों पर नीति प्रक्रिया के पड़े प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

7.6 शब्दावली

कोरोना वायरस (Coronavirus) : यह एक विषाणु है, जो जानवर से लेकर मनुष्यों तक फैलता है, जिसके लक्षण मनुष्य में होते है जैसे– नाक बहना, सांस लेने में समस्या, छींकना और अंत में घातक हो सकता है यदि कोई निवारक उपाय नहीं किए जाते हैं।

''कोरोना वायरस'' नाम लैटिन शब्द कोरोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है ''ताज'' या ''पुष्पांजलि (माला)'' जो खुद ग्रीक ''माला'' पुष्पांजलि'' से लिया गया है। इसका नए रूप को कोविड 19 कहा जाता है, जो मार्च 2020 में जंगल की आग की तरह दुनिया भर में फैल गया है।

सेवा अनुबंध (Service Contract) : इसका अर्थ है सरकार द्वारा एक नेटवर्क को सक्रिय करने के अनुबंध का उपयोग।

वैश्वीकरण (Globalisation) : यह शब्द वैश्विक बाजार स्थान का सरपट विस्तार से समानार्थ है।

7.7 संदर्भ लेख

Farazmand, A. & Pinkowski, J. (Eds.) (2007). *Globalization, Governance and Public Administration.* New York: Taylor and Francis.

Giddens, A. (2007, October 28). Globalization: Theme tune of our times. *The Tribune*.

Hankock, G. (1989). *Lords of Poverty.* New York: Atlantic Monthly Press.

LeFeber, W. (1984). *Inevitable Revolutions.* New York: Norton.

Martin, B. (1993). *In the Public Interest: Privatisation and Public Sector Reform.* London: Zed Books Ltd.

OECD. (1993). *Public Management Developments: Survey 1991.* OECD: Paris.

Osborne, D. & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government.* New York: Addison – Wesley.

Scholte, J.A. (1997). Global Capitalism and the State. *International Affairs.* 3, 427-452.

Self, P. (1993). *Government by the Market.* London: Macmillon.

Stever, J. (1988). *The End of Public Administration*. New York: Transnational Publication.

Tullock, G. (1965). *The Politics of Bureaucracy.* Washington: Public Affairs Press.

World Bank. (1992), Governance and the External Factor. *Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics,* 1991. Washington: World Bank.

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:

- नई आर्थिक नीति 1991 में आरंभ की गई थी।
- एक नीति के रूप में यह माना जाता हैं कि बाजार की ताकतें सरकार के नियंत्रण की अपेक्षा अधिक प्रभावी तरीकें से अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन कर सकती हैं।

- उदारीकरण नीति की महत्वपूर्ण भूमिका सरकारी नियंत्रणों को आसान बनाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
- उदारीकरण ने विदेशी कंपनियों और निवेशों के लिए आर्थिक सीमएँ खोल दी हैं।
- इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को बढ़ाना और देश के वैश्विक बाजार की सीमाओं में विस्तार करना है।

2. आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहिएः

- 'सरकार की पुर्रचना' की आवश्यकता के लिए समर्थकों ने तर्क दिया है कि प्रबंधकीय बदलावों में अधिक बाजार संचालित विकेन्द्रीकरण नीति प्रक्रिया शामिल की जाए।
- निजीकरण में केंद्र सरकार का पुनर्गठन और लोक उद्यमों का पुनर्गठन और विकेन्द्रीकरण शामिल हैं।
- समस्त ओ-ई-सी-डी- देशों में नीतियों की रक्षा की तस्वीर इस प्रकार बनाई गई है कि निजी क्षेत्र का अनुसरण लोक क्षेत्र करे और लोक सेवाओं का वितरण नागरिकों के पास लाया जाए।
- निजीकरण सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है।
- यह लोक क्षेत्र कंपनियों के कार्यभार को कम करता है।
- सरकारी संगठनों की दक्षता को बढ़ाता है।
- उपभोक्ताओं को बेहतर और अच्छी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है।
- निजीकरण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है।

बोध प्रश्न 2

1. आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहिएः

- 'वैश्वीकरण' शब्द कोई क्षेत्रीय सीमाओं को नहीं पहचानता और विश्व के सम्पूर्ण क्षेत्रों में होने का दावा करता है।
- यह विश्व शक्तियों, आर्थिक प्रणालियों और प्रशासनिक प्रथाओं के एकीकरण और अभिसरण को दर्शाता है।
- वैश्वीकरण को देशों के बीच बाधाओं को कम करने और निकट आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संपर्क को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है।
- राज्य के कार्यों के दृष्टिकोण में एक बदलाव है।
- ट्रासंवर्ल्ड निगमों द्वारा शासित बाजार– संचालित और निगम– राज्य के लिए राज्य और लोक प्रशासन का एक वैश्विक परिवर्तन है।
- वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता, लोकतंत्र और अधिकांश विकासशील देशों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है।

- वैश्वीकरण को पारिस्थितिक प्रणाली के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है।
- अधिकांश विकासशील और विकसित राष्ट्र प्राकृतिक पर्यावरण के सरंक्षण के लिए बहुत कम ध्यान देते हैं।
- दुनिया भर में गरीबी और असमानता को बढ़ाने के लिए वैश्वीकरण की आलोचना की गई है।
- यह तकनीकी नवाचारों के माध्यम से अधिक बेरोजगारी का कारण बना है और इसने कर सब्सिडी और कर व्यय के साथ शासन प्रणाली को खाली कर दिया है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY